हिन्दी साप्ताहिक R.N.I. No. UPHIN/2022/83621

जनता का सच

वर्ष 04 अंक 35 | लखनऊ शनिवार 06 सितम्बर 2025 | पृष्ठ 04 मूल्य 2 रूपया

युवा शक्ति बनाएगी देश को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था-योगी

बालजी दैनिक

लखनऊ ।उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक बन गया है और अगले दो वर्षों में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए तैयार है, जबकि वर्तमान में यह चौथे स्थान पर है। मुख्यमंत्री आईआईटी कानपुर में 'समन्वय' के माध्यम से उद्योग-अकादमिक संपर्क कार्यक्रम में छात्रों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सुरक्षा और स्थिरता पर विभिन्न तकनीकी सत्र आयोजित किए जाएँगे और उन सभी मुद्दों पर चर्चा की जाएगी, जिन्हें लेकर आज आम नागरिक समाज, देश और दुनिया चिंतित है और उनका लाभ उठाकर आगे बढ़ना चाहता है।

भारत की ऐतिहासिक आर्थिक स्थिति पर प्रकाश डालते हुए, मुख्यमंत्री ने कहा कि वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में भारत का योगदान 25% था। एक सदी बाद, भारत दूसरे नंबर पर पहुँच गया, जबकि चीन शीर्ष पर रहा; हालाँकि, पिछले 150-200 वर्षों में, एक महत्वपूर्ण घटना घटी जिसके कारण भारत की रैंकिंग में लगातार गिरावट आई। 1947 तक, वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में भारत का योगदान केवल 2 प्रतिशत रह गया। उन्होंने आगे कहा कि पिछले 11 वर्षों में भारत में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं और अब यह विश्व स्तर पर सबसे तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक बनकर उभरा है।

उन्होंने आगे कहा कि आज हम दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं और अगले दो वर्षों में हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएँगे। आप सभी भारत को दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने में बड़ी भूमिका निभाएँगे। इस बीच, मंगलवार को चेन्नई में सिटी यूनियन बैंक के 120वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए, अध्यक्ष द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि किसानों का सशक्तिकरण और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मज़बूत करना भारत के बैंकिंग क्षेत्र की प्राथमिकता होनी चाहिए। अध्यक्ष मुर्मू ने यह भी कहा कि बैंक एमएसएमई को विकास के इंजन में बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। उन्होंने कहा, 'स्टार्ट-अप से लेकर स्मार्ट शहरों तक, ऐसे कई क्षेत्र हैं जिनमें बैंक मदद कर सकते हैं। बैंक एक विकसित भारत के निर्माण में सक्रिय भागीदार बन सकते हैं।' वित्तीय सेवाओं में उल्लेखनीय प्रगति के बावजूद, राष्ट्रपति ने बताया कि डिजिटल साक्षरता, इंटरनेट पहुँच और वित्तीय जागरूकता जैसे क्षेत्रों में चुनौतियाँ बनी हुई हैं।

ईवी चार्जिंग स्टेशन का शुभारंभ

लखनऊ । उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने आज इकोप्लग एनर्जी इंडिया लिमिटेड के अत्याधुनिक विद्युत वाहन चार्जिंग स्टेशन एवं एसी चार्जर्स की श्रृंखला का भव्य शुभारंभ किया। इसी अवसर पर राज्य के अधिकृत भंडारण केंद्र ई-पृथ्वी ग्रीन प्रा. लि. का भी उद्घाटन किया गया।

उप मुख्यमंत्री ने कहा कि 'यह पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हरित ऊर्जा संकल्प को साकार करने की दिशा में एक अहम कदम है।' उन्होंने नागरिकों से विद्युत वाहन अपनाने की अपील भी की। कंपनी निदेशक राजपाल यादव, जानकीदास वैष्णव, इन्दर मोहन सचदेवा व पुनीत तलवार उपस्थित रहे। साथ ही राज्यभर के विक्रेता, उपभोक्ता और मीडिया प्रतिनिधि भी कार्यक्रम में शामिल हुए। ई-पृथ्वी ग्रीन के निदेशक प्रेम सागर त्रिपाठी ने इकोप्लग के नवीनतम चार्जिंग समाधानों का प्रदर्शन किया।

इकोप्लग का उद्देश्य है - भारत को हरित, स्वच्छ और प्रदूषणमुक्त परिवहन की दिशा में अग्रसर करना।

असम से 24 बांग्लादेशी घुसपैठियों को वापस भेजा गया : हिमंत

असम-मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा ने कहा कि राज्य में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों के खिलाफ चलाये जा रहे अभियान के तहत मंगलवार को 24 घुसपैठियों को वापस भेज दिया गया। शर्मा ने व्यंग्यात्मक लहजे में, वापस भेजे गए घुसपैठियों को 'सुखद यात्रा' की शुभकामनाएं दीं। मुख्यमंत्री ने वापस भेजे गए बांग्लादेशियों की तस्वीर सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर साझा किया और तंज कसते हुए कहा, " बेचारे लोग भटक गए थे। हमने उन्हें रास्ता दिखाया और घर भेज दिया।" उन्होंने कहा,"अक्सर कुछ लोग भूल जाते हैं कि उनका निवास कहां है और वे भटक कर सीमा के इस ओर आ जाते हैं। लेकिन एक दयालु राष्ट्र होने के नाते, हम उन्हें वापस भेज देते हैं।" शर्मा ने कहा कि दिन में 24 बांग्लादेशियों को वापस भेज दिया गया है। असम पुलिस ने बिना वैध दस्तावेजों के रह रहे अवैध प्रवासियों, विशेषकर बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ राज्यव्यापी कार्रवाई शुरू की है।

बुढ़वा मंगल पर श्री पंचमुखी हनुमान मंदिर विनायकपुर में नेशनल मीडिया प्रेस क्लब व विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के संयुक्त तत्वावधान में हुआ कार्यक्रम

सुंदरकांड, भजन कीर्तन, हनुमान चालीसा पाठ, साधु समागम व सम्मान समारोह का धूमधाम से हुआ आयोजन

बालजी दैनिक

कानपुर- श्री पंचमुखी हनुमान मंदिर विनायकपुर, कानपुर में नेशनल मीडिया प्रेस क्लब व विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के संयुक्त तत्वावधान में बुढ़वा मंगल के शुभ अवसर पर सुंदरकांड, भजन कीर्तन, हनुमान चालीसा पाठ के साथ साथ साधु समागम व सम्मान समारोह का बड़ी श्रद्धा से किया गया आयोजन। आपको बता दे बुढ़वा मंगल, जिसे 'बड़ा मंगल' भी कहते हैं, इस दिन हनुमान जी का प्रभु श्रीराम से मिलन हुआ था। इसके साथ ही एक प्रचलित कथा के अनुसार, महाभारत काल में महाबली भीम के घमंड को दूर करने के लिए हनुमान जी ने बूढ़े बंदर का रूप धारण किया था, जिससे इस दिन को बुढ़वा मंगल भी कहा जाने लगा। इस दिन हनुमान जी की पूजा करने से भक्तों को विशेष पुण्य मिलता है और सभी

मनोकामनाएं पूरी होती हैं। उक्त कार्यक्रम का आयोजन नेशनल मीडिया प्रेस क्लब के मण्डल मीडिया प्रभारी संतोष कुमार कुशवाहा द्वारा विगत कई वर्षों से आयोजित किया जा रहा है। जिसमें कई साधु संतों और महंत लोगों का आगमन हुआ और कई समाजसेवी लोगों ने आकर बाबा के दर्शन किए । मंदिर में हो रहे भजन कीर्तन का गायन कर रही ललिता सिंगर की मधुर आवाज से भक्त मंत्र मुग्ध हो गए। सभी अतिथियों का कार्यक्रम आयोजक सज्जन कुशवाहा द्वारा माला फूल, श्रीराम पट्टिका भेंट कर जोरदार स्वागत व सम्मान किया गया । कार्यक्रम में प्रमुख रूप से मनोज आनंद गोल्डन बाबा जी, भारत आनंद ब्रह्मचारी जी नागेश्वर धाम आश्रम, संजय गिरी नागा बाबा, गोविंद तिवारी जी महाराज, कल्याणपुर बीजेपी मंडल अध्यक्ष जनक सिंह चौहान, गीता नगर मंडल अध्यक्ष राजेश जोशी, नगर निगम अध्यक्ष मुन्ना हजारिया, नेशनल मीडिया प्रेस क्लब राष्ट्रीय अध्यक्ष एम डी शर्मा, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह, प्रदेश मंत्री कृष्णा शर्मा, प्रदेश कोषाध्यक्ष डॉक्टर बलबीर कपाड़िया, मण्डल अध्यक्ष एडवोकेट अवधेश सिंह तोमर व एडवोकेट प्रशांत मिश्रा, पिंटू श्रीवास्तव, रचित कश्यप, सचिन यादव, करन मौर्य, ललिता सिंगर, सोनू कुशवाह, अनिल सिंह चौहान, चरन पाल, प्रवीन तोमर सहित सैकड़ों लोग कार्यक्रम में रहे उपस्थित और बाबा के दर्शन कर प्रसाद ग्रहण किया ।

देवदासी महिलाओं का सर्वेक्षण की तैयारी

कर्नाटक सरकार सितंबर के पहले सप्ताह से देवदासी प्रथा से जुड़ी महिलाओं का एक नया सर्वेक्षण शुरू करने की संभावना है। लंबे समय से लंबित इस सर्वेक्षण का उद्देश्य उन देवदासी महिलाओं की पहचान करना है जिन्हें अभी तक मौजूदा कल्याण और पुनर्वास कार्यक्रमों में शामिल नहीं किया गया है। पिछला राज्यव्यापी सर्वेक्षण 2008 में किया गया था, जिसमें 40,000 से ज़्यादा देवदासियों की पहचान की गई थी। गौरतलब है कि कर्नाटक में देवदासी प्रथा पर 1984 में आधिकारिक रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया था।

देवदासी प्रथा सदियों पुरानी एक प्रथा है जिसमें छोटी लड़कियों को मंदिरों में समर्पित कर दिया जाता था और माना जाता था कि उनका विवाह किसी देवता या मंदिर के देवता से हुआ है।

यूरोपीय संघ-भारत मुक्त व्यापार समझौते के जल्द ही संपन्न हो जाने की उम्मीदः जयशंकर

नई दिल्ली-विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बुधवार को कहा कि भारत चाहता है कि यूरोपीय संघ के साथ मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) के लिए उसकी बातचीत जल्द ही किसी निर्णायक नतीजे पर पहुंचे।

जयशंकर ने जर्मनी के अपने समकक्ष जोहान वेडफुल के साथ व्यापक वार्ता के बाद एक संयुक्त प्रेस वार्ता में यह टिप्पणी की। विदेश मंत्री ने कहा कि वार्ता में अर्थव्यवस्था, जलवायु परिवर्तन, रक्षा, और प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया गया। उन्होंने कहा, "हम भारत के साथ व्यापार को दोगुना करने संबंधी जर्मनी के लक्ष्य की सराहना करते हैं।" विदेश मंत्री ने निर्यात नियंत्रण के मुद्दों को सुलझाने के लिए भी जर्मनी की प्रशंसा की। जयशंकर ने सेमीकंडक्टर क्षेत्र में भारत के साथ सहयोग के लिए जर्मनी की दिलचस्पी का भी स्वागत किया। विदेश मंत्री ने कहा कि वेडफुल ने उन्हें बताया कि जर्मनी भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के समर्थन में अपना पूरा जोर लगायेगा। जयशंकर ने कहा कि भारत और जर्मनी हरित हाइड्रोजन क्षेत्र में भी सहयोग की संभावनाएं तलाश रहे हैं। उन्होंने कहा कि जर्मनी के साथ भारत के संबंध बहुत महत्वपूर्ण हैं और ये उल्लेखनीय रूप से आगे बढ़ रहे हैं।

बृहत बेंगलुरु प्राधिकरण का गठन ऐतिहासिक कदम : शिवकुमार

बेंगलुरु-कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने मंगलवार को बृहत बेंगलुरु प्राधिकरण (जीबीए) की औपचारिक स्थापना और बेंगलुरु के नाम पर पांच नए नगर निगमों के गठन की घोषणा की। उन्होंने इसे शासन का विकेंद्रीकरण करने और विकास कार्यों में तेजी लाने के उद्देश्य से एक 'ऐतिहासिक निर्णय' बताया।

शिवकुमार ने यहां संवाददाताओं से कहा, "आज एक विशेष दिन है, जब जीबीए के बेंगलुरु नाम से पांच निगम अस्तित्व में आए हैं।" नए निगमों में बेंगलुरु मध्य, बेंगलुरु उत्तर, बेंगलुरु दक्षिण, बेंगलुरु पूर्व और बेंगलुरु पश्चिम शामिल हैं। उन्होंने स्पष्ट किया, "हमने इनमें से किसी का भी नाम किसी व्यक्ति के नाम पर नहीं रखा है।" शिवकुमार ने कहा कि प्रत्येक निगम के आयुक्त तुरंत कार्यभार संभालेंगे और सीधे राजस्व संग्रह करना शुरू करेंगे।

पीएम मोदी की दिवंगत मां का अपमान, स्मृति ईरानी बोलीं- पूरा देश आक्रोश में, विपक्ष को जवाब मिलेगा

नई दिल्ली-पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने बिहार में एक जनसभा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी दिवंगत मां पर की गई कथित अपमानजनक टिप्पणियों को लेकर विपक्ष पर निशाना साधा। स्मृति ईरानी ने कहा कि कथित टिप्पणी 'पूरे देश को आहत करती है' क्योंकि पीएम मोदी की मां का राजनीति से कोई संबंध नहीं था और उन्होंने गरीबी में संघर्ष किया था। एक वीडियो संदेश में, भाजपा नेता ने कहा कि बिहार के एक राजनीतिक मंच पर विपक्षी नेताओं द्वारा पीएम मोदी की दिवंगत मां का अपमान पूरे देश को आहत करता है। उस मां का राजनीति से कोई संबंध नहीं था, जिस मां ने अपने परिवार की रक्षा के लिए गरीबी में संघर्ष किया, जो मां अब हमारे बीच नहीं हैं - ऐसी मां का अपमान हम सभी को पीड़ा देता है।

ईरानी ने कहा कि मुझे विश्वास है कि देश और बिहार की माताएँ और बहनें इस अपमान का विपक्ष को करारा जवाब देंगी। इससे पहले, बिहार के उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कथित अपमानजनक टिप्पणी के लिए माफी नहीं मांगने पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और राजद विधायक तेजस्वी यादव की आलोचना की। सिन्हा ने एएनआई से कहा कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव प्रधानमंत्री मोदी की दिवंगत माँ का अपमान कर रहे हैं। उनकी पार्टी में किसी को शर्म नहीं आती। किसी ने माफ़ी नहीं मांगी। भारतीय जनता पार्टी (आईएनडीआई) गठबंधन महिलाओं का अपमान करता है।

उन्होंने आगे कहा कि इस तरह के नकारात्मक बयान विकसित बिहार के सामाजिक सौहार्द को भ्रमित करने, भड़काने और कमज़ोर करने के लिए दिए जा रहे हैं। ये राक्षसी मानसिकता के लोग हैं। इन्हें विकास और महिला सशक्तिकरण की कोई परवाह नहीं है। बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इस तरह की टिप्पणियों से लोकतंत्र का अपमान करने के लिए भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की आलोचना की।

कानून व्यवस्था पर बड़ा फैसला

उपद्रवियों पर होगी सख्त कार्रवाई-धामी

बालजी दैनिक

देहरादून-उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को सचिवालय में एक उच्चस्तरीय बैठक की और राज्य की कानून-व्यवस्था, सड़कों की स्थिति, सेवा पखवाड़ा और अन्य जनहित से जुड़े मुद्दों की समीक्षा की। बैठक में अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि जनता के लिए सुचारू, सुरक्षित और पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए कि राज्य में कानून-व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए।

पुष्कर सिंह धामी ने कहा सभी संवेदनशील स्थानों पर सीसीटीवी कैमरों से नियमित निगरानी सुनिश्चित की जाए। राज्य की सीमाओं पर सघन

चेकिंग अभियान चलाया जाए। पुलिस द्वारा रात्रि गश्त को और प्रभावी बनाया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि मानसून के बाद सड़कों को गड्ढामुक्त करने के लिए विशेष अभियान चलाया जाए। बरसात के बाद सड़कों के सुधार और गड्ढामुक्ति के लिए टेंडर प्रक्रिया अभी पूरी कर ली जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन 17 सितंबर से गांधी जयंती 2 अक्टूबर तक पूरे प्रदेश में सेवा पखवाड़ा मनाया जाएगा। इस अवसर पर सभी जिलों में सेवा, जनजागरूकता एवं जनहित से जुड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाएँगे। उन्होंने अधिकारियों को प्रत्येक जिले के लिए एक विस्तृत कार्ययोजना तैयार करने और उसे समयबद्ध तरीके से क्रियान्वित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि वे स्वयं सड़क मार्ग से विभिन्न जिलों का दौरा करेंगे और व्यवस्थाओं का प्रत्यक्ष जायजा लेंगे। मुख्यमंत्री ने नमक में रेत मिलाए जाने की शिकायत को गंभीरता से लिया और तत्काल नमूने लेकर जाँच के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जाँच में जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

प्रियंका गांधी ने वायनाड में सरकारी मेडिकल कॉलेज को मंजूरी का स्वागत किया

वायनाड-कांग्रेस नेता एवं वायनाड से सांसद प्रियंका गांधी वाद्रा ने वायनाड में एक सरकारी मेडिकल कॉलेज की मंजूरी का बुधवार को स्वागत करते हुए कहा कि लंबे समय से संजोया गया यह सपना सच हो गया है।

राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (एनएमसी) ने मंगलवार को केरल के वायनाड और कासरगोड जिलों में दो नये सरकारी मेडिकल कॉलेज को मंजूरी दी। प्रियंका गांधी वाद्रा ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, "वायनाड के लाखों लोगों के अनुरोध, राहुल गांधी के निरंतर प्रयास और मामले में तेजी लाने के हमारे सभी प्रयासों का फल मिला है।" उन्होंने कहा, "हमारी अपीलों को सुनने और वायनाड के नागरिकों के लिए मजबूत स्वास्थ्य सेवा की दिशा में एक स्वागत योग्य कदम उठाने के लिए सभी संबंधित पक्षों का हार्दिक धन्यवाद।" उन्होंने आशा व्यक्त की कि राज्य सरकार निर्माण कार्य में तेजी लाने तथा कॉलेज को यथाशीघ्र चालू करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगी। प्रियंका ने कहा, "आइए, हम सब मिलकर उन लोगों के विकास और प्रगति के साझा लक्ष्य की ओर काम करें जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है।"

अपशब्द कहने वाले का कांग्रेस पार्टी से कोई लेना-देना नहीं: पायलट

नई दिल्ली-कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट ने मंगलवार को कहा कि प्रधानमंत्री की मां के लिए कथित तौर पर अपशब्द का इस्तेमाल करने वाले का कांग्रेस पार्टी से कोई लेना-देना नहीं है।

पायलट ने साथ ही कहा कि अगर किसी ने ऐसा किया है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए लेकिन इस मुद्दे पर बहुत अधिक राजनीति नहीं होनी चाहिए। पायलट ने यहां मीडिया से कहा, " हम लोग उस कांग्रेस पार्टी से हैं जो 130 साल से संस्कार, संयम और अनुशासन वाली पार्टी है।... उसका हमारी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। अब किसी

के मंच पर कोई चढ़ जाए और (अपशब्द) बोले दे तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए।"

पायलट ने कहा कि विकास के मुद्दे पर बात होनी चाहिए। पायलट ने कहा कि अपशब्दों के इस्तेमाल पर सबकी एक राय है कि बुजुर्ग और माता-पिता हम सबके लिए सम्मानित हैं और सब उनकी इज्जत करते हैं, इस पर बहुत ज्यादा राजनीति नहीं करनी चाहिए। दरअसल बिहार में कांग्रेस की 'वोटर अधिकार यात्रा' के दौरान दरभंगा में एक स्थानीय कांग्रेस नेता के मंच से 25 वर्षीय युवक ने अभद्र का उपयोग किया था। युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है। कांग्रेस और राजद नेताओं ने कहा है कि घटना में उनकी कोई भूमिका नहीं है।

विफल होती नजर आ रही है योगी सरकार की गड्ढा मुक्त योजना

नीमचेना - चतुरैया मार्ग पर सड़क टूटी सड़क टूटने से बना गड्ढा, पानी भरने से वाहन चालकों को परेशानी

ब्यूरो रिपोर्ट अनूप पाण्डेय

सीतापुर में महोली ब्लॉक के नीमचेना चतुरैया जाने वाले मार्ग पर पुल भी टूट गया सड़क टूट गई है। इस मार्ग पर बना गड्ढा वाहन चालकों के लिए समस्या बन गया है। गड्ढे में पानी भर जाने से स्थिति और भी जटिल हो गई है। यह रास्ता नीमचेना चतुरैया बीरमपुर नीमचेनी कस्ता मार्ग से जोड़ती है आदि गांव की तरफ जाता है। मार्ग का यह हिस्सा चतुरैया से होते हुए नीमचेना की ओर जाता है। टूटी सड़क के कारण दोपहिया वाहन चालकों को विशेष सावधानी बरतनी पड़ती है। मोड़ पर सड़क का टूटा होना दुर्घटना का कारण बन सकता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस मार्ग से रोजाना सैकड़ों वाहन गुजरते हैं। पूरी रोड पर बने गड्ढे में पानी भरा होने से वाहन चालकों को गड्ढे की गहराई का अंदाजा नहीं लग पाता। इससे छोटे वाहनों के लिए यह स्थान विशेष रूप से खतरनाक बन गया है। कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है क्योंकि यूपी रोडवेज बस भी इधर से ही गुजरती है जो सीतापुर से आती है।

जरूरी है समान नागरिकता

डॉ. निवेदिता शर्मा

भारत के लोकतांत्रिक ढांचे के सामने इस समय सबसे गंभीर सवाल यह है कि क्या देश की बच्चियों और बच्चों की सुरक्षा उनकी धार्मिक पहचान और पर्सनल लॉ से तय होगी या फिर संविधान और संसद द्वारा बनाए गए कानून सभी पर समान रूप से लागू होंगे। यह सवाल केवल कानूनी तकनीक या न्यायिक व्याख्या तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज के भविष्य और राष्ट्र की दिशा तय करने वाला है। हाल के वर्षों में विभिन्न उच्च न्यायालयों ने मुस्लिम पर्सनल लॉ का हवाला देते हुए यह कहा कि यदि कोई मुस्लिम लड़की यौवन प्राप्त कर चुकी है तो उसका विवाह, भले ही वह 18 वर्ष से कम उम्र की हो, वैध माना जाएगा। इन निर्णयों के पीछे तर्क दिया गया कि शरीयत के अनुसार यौवन विवाह की क्षमता प्रदान करता है। परंतु यह व्याख्या बच्चों के अधिकारों, संसद द्वारा बनाए गए पॉक्सो कानून और संविधान के मूलभूत सिद्धांतों को सीधी चुनौती देती है। संसद ने 2012 में बच्चों को यौन अपराधों से बचाने के लिए पॉक्सो अधिनियम पारित किया। इसमें साफ-साफ परिभाषा दी गई कि 18 वर्ष से कम उम्र का हर व्यक्ति बच्चा है और उसके साथ किसी भी प्रकार का यौन संबंध अपराध है, चाहे वह विवाह के नाम पर ही क्यों न हो। जब अदालतें पर्सनल लॉ के आधार पर इस प्रावधान को दरकिनार करती हैं, तो केवल कानून का उल्लंघन नहीं होता, बल्कि यह एक ऐसी दोहरी व्यवस्था पैदा करता है, जो संविधान की समानता की गारंटी को कमजोर करती है। संवैधानिक कसौटी और समानता का सवाल: संविधान के अनुच्छेद 14 सभी को समानता का अधिकार देते हैं, अनुच्छेद 15(3) महिलाओं और बच्चों को विशेष संरक्षण प्रदान करता है और अनुच्छेद 21 हर नागरिक को गरिमा और जीवन का अधिकार सुनिश्चित करता है। ये अधिकार धर्म या परंपरा पर निर्भर नहीं हैं। जब हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध या पारसी बच्चियों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 18 वर्ष है, लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत इसे 15 या 16 वर्ष में वैध ठहराया जाता है, तो यह नागरिकता की समानता के सिद्धांत पर सीधा आघात है। राष्ट्र तभी ÷एक कानून, एक सुरक्षा÷ की दिशा में आगे बढ़ सकता है, जब सभी बच्चियों को उनकी धार्मिक पहचान से परे समान सुरक्षा मिले। अन्यथा भारत दोहरी व्यवस्था वाला देश बन जाता है, जहाँ एक समुदाय की बेटी को राज्य का संरक्षण मिलता है और दूसरी बेटी उसी उम्र में वैवाहिक बंधन के नाम पर असुरक्षित छोड़ दी जाती है। विधिक ढांचा और न्यायालयों की व्याख्या: देश में बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 और पॉक्सो अधिनियम, 2012 दोनों स्पष्ट रूप से 18 वर्ष की आयु से पहले विवाह और यौन संबंधों को अपराध घोषित करते हैं। इतना ही नहीं, उच्चतम न्यायालय ने 2017 में इंडिपेंडेंट थॉट बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के ऐतिहासिक फैसले में कहा कि यदि पत्नी की आयु 18 वर्ष से कम है तो उसके साथ यौन संबंध बलात्कार के समान अपराध होगा। इस फैसले ने परंपरा को बच्चों की सुरक्षा से ऊपर रखने से इनकार किया और संविधान की सर्वोच्चता को स्थापित किया। बावजूद इसके, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय जैसे कुछ न्यायालयों ने मुस्लिम पर्सनल लॉ का हवाला देकर नाबालिग विवाह को मान्यता दी। वहीं, दिल्ली और केरल उच्च न्यायालय ने साफ कहा कि पॉक्सो सभी व्यक्तिगत कानूनों से ऊपर है। यह विरोधाभास अपने आप में इस आवश्यकता को रेखांकित करता है कि अब सर्वोच्च न्यायालय को संविधान पीठ गठित कर स्पष्ट और सर्वमान्य निर्णय देना चाहिए। एनसीपीसीआर और न्यायपालिका का रुख: बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए संसद ने राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) बनाया। यही संस्था जब सुप्रीम कोर्ट में पहुंची तो उसकी याचिका को यह कहकर खारिज कर दिया गया कि वह ÷अजनबी÷ है और मामले में उसकी लोकस स्टैंडी नहीं है। यह स्थिति अत्यंत चिंताजनक है। अगर बच्चों की वैधानिक संरक्षक संस्था को ही न्यायपालिका सुनने को तैयार न हो, तो फिर बच्चियों की आवाज कौन उठाएगा? संसद को चाहिए कि वह एनसीपीसीआर को यह अधिकार स्पष्ट रूप से प्रदान करे कि वह सीधे सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में बच्चों के अधिकारों से जुड़े मामलों में हस्तक्षेप कर सके। बाल विवाह आज भी सामाजिक चुनौती: यह प्रश्न अक्सर मुस्लिम पर्सनल लॉ तक सीमित कर दिया जाता है, लेकिन सच्चाई यह है कि बाल विवाह पूरे देश में एक व्यापक सामाजिक समस्या है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस-5) के अनुसार भारत में 23 प्रतिशत लड़कियां 18 वर्ष से पहले विवाह कर लेती हैं। ग्रामीण इलाकों में यह दर और अधिक है। पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड और असम जैसे राज्यों में बाल विवाह की दर 30 प्रतिशत से ऊपर है। इन आँकड़ों से साफ है कि समस्या किसी एक धर्म या समुदाय की नहीं, बल्कि सामाजिक संरचना और पिछड़ेपन से जुड़ी है। लेकिन जब न्यायालय पर्सनल लॉ के आधार पर बाल विवाह को वैध ठहराते हैं, तो यह सामाजिक समस्या और गहरी हो जाती है। अंतरराष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य और भारत की प्रतिबद्धता: भारत ने संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार संधि (यूएनसीआरसी) पर 1992 में हस्ताक्षर किए। इस संधि के अनुसार 18 वर्ष से कम आयु का हर व्यक्ति बच्चा है और उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करना राज्य का दायित्व है। भारत ने सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी-5.3) के तहत 2030 तक बाल विवाह समाप्त करने का संकल्प भी लिया है। महत्वपूर्ण यह है कि कई मुस्लिम-बहुल देशों जैसे इंडोनेशिया, मलेशिया और बांग्लादेश ने विवाह की न्यूनतम आयु 18 वर्ष तय की है। बांग्लादेश ने 2017 में बाल विवाह निषेध अधिनियम लाकर नाबालिग विवाह को अपराध घोषित किया। यह स्पष्ट करता है कि यह धर्म का नहीं, बल्कि बच्चों की सुरक्षा और सामाजिक सुधार का वैश्विक एजेंडा है। मुस्लिम समाज के भीतर सुधार की आवाजः मुस्लिम समाज के भीतर भी बड़ी संख्या में लोग बाल विवाह का विरोध कर रहे हैं। अनेक मुस्लिम महिला संगठन और सामाजिक कार्यकर्ता इस बात पर जोर देते हैं कि इस्लाम बाल विवाह को बढ़ावा नहीं देता। पैगंबर मोहम्मद की शिक्षाओं में विवाह परिपक्वता और सहमति पर आधारित बताया गया है, न कि केवल शारीरिक यौवन पर। इसलिए सुधार की मांग बाहर से थोपी हुई नहीं, बल्कि समाज के भीतर से भी आ रही है। कम उम्र में विवाह केवल कानूनी समस्या नहीं है, बल्कि इसके सामाजिक और स्वास्थ्य पर दूरगामी दुष्परिणाम होते हैं। किशोरावस्था में गर्भधारण से मातृ मृत्यु दर कई गुना बढ़ जाती है। जल्दी विवाह से बच्चियों की शिक्षा अधूरी रह जाती है और आत्मनिर्भर बनने का सपना टूट जाता है। नाबालिग मातृत्व से जनसंख्या वृद्धि की गति तेज होती है, जिससे संसाधनों पर बोझ बढ़ता है। खेल, शिक्षा, कला और विज्ञान में संभावित प्रतिभाएँ असमय विवाह के कारण घर की चारदीवारी तक सीमित हो जाती हैं। मानसिक स्वास्थ्य पर भी गहरा असर पड़ता है।

सम्पादकीय

मोदी-जिनपिंग की मुलाकात

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी दो-राष्ट्र की यात्रा के दूसरे और अंतिम चरण में जापान से चीनी शहर तियानजिन पहुंचे हैं। यहां पीएम मोदी मुख्य रूप से 31 अगस्त और 1 सितंबर को शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। हालांकि, रविवार को चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ उनकी निर्धारित बैठक वाशिंगटन के टैरिफ विवाद के मद्देनजर और भी महत्वपूर्ण हो गई है, जिसका असर दुनिया भर की लगभग सभी प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं पर पड़ा है। इस वार्ता में पीएम मोदी और शी भारत-चीन आर्थिक संबंधों का जायजा लेने और पूर्वी लद्दाख सीमा विवाद के बाद गंभीर तनाव में आए संबंधों को और सामान्य बनाने के लिए कदमों पर विचार-विमर्श करेंगे। प्रधानमंत्री अपनी दो-राष्ट्र यात्रा के दूसरे और अंतिम चरण में जापान से इस चीनी शहर पहुंचे हैं। पीएम मोदी शिखर सम्मेलन से इतर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और कई अन्य नेताओं के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी कर सकते हैं। तियानजिन की अपनी यात्रा से पहले पीएम मोदी ने कहा कि विश्व आर्थिक व्यवस्था में स्थिरता लाने के लिए भारत और चीन का मिलकर काम करना जरूरी है। जापान के योमिउरी शिंबुन को दिए एक साक्षात्कार में पीएम मोदी ने कहा कि भारत और चीन के बीच स्थिर पूर्वानुमानित और सौहार्दपूर्ण द्विपक्षीय संबंध क्षेत्रीय और वैश्विक शांति एवं समृद्धि पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। इससे पहले शुक्रवार को प्रकाशित साक्षात्कार में पीएम मोदी ने कहा, %विश्व अर्थव्यवस्था में मौजूदा अस्थिरता को देखते हुए दो प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के रूप में भारत और चीन के लिए विश्व आर्थिक व्यवस्था में स्थिरता लाने के लिए मिलकर काम करना भी जरूरी है।% पीएम मोदी की चीन यात्रा चीनी विदेश मंत्री वांग यी की भारत यात्रा के एक पखवाड़े से भी कम समय बाद हो रही है। विदेश मंत्री एस जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के साथ वांग की व्यापक वार्ता के बाद दोनों पक्षों ने दोनों पक्षों के बीच स्थिर, सहयोगात्मक और दूरदर्शी संबंधों के लिए कई उपायों की घोषणा की थी। पिछले कुछ महीनों में भारत और चीन ने अपने संबंधों को फिर से स्थापित करने के लिए कई कदम उठाए हैं। जो जून 2020 में गलवां घाटी में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच हुई घातक झड़पों के बाद गंभीर तनाव में आ गए थे। प्रधानमंत्री ने आखिरी बार जून 2018 में एससीओ शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए चीन का दौरा किया था। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अक्तूबर 2019 में दूसरे अनौपचारिक शिखर सम्मेलन के लिए भारत का दौरा किया था।

प्रेम, भक्ति एवं शक्ति की अनंत ज्योति हैं राधाजी

-ललित गर्ग-

भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी का दिन भारतीय संस्कृति में प्रेम, भक्ति, शक्ति और समर्पण का अनोखा पर्व लेकर आता है-यह है राधाष्टमी। इसे राधा रानी का जन्मोत्सव माना जाता है। यह केवल किसी भक्ति की विशेष नारी चरित्र के जन्मोत्सव का पर्व नहीं, बल्कि उस दिव्य शक्ति की अभ्यर्थना है जिसने स्वयं श्रीकृष्ण के जीवन को एक अनूठी ऊंचाई दी। इस दिन भक्त राधा और श्रीकृष्ण की पूजा करते हैं, व्रत रखते हैं और उनकी कृपा से सुख-समृद्धि व सौभाग्य की प्राप्ति की कामना करते हैं। ब्रजभूमि, खासकर बरसाना में इसे बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। राधाजी प्रेम, भक्ति और श्रीकृष्ण के भीतर छिपी शक्ति का प्रतीक हैं; वह प्रेम की पराकाष्ठा, भक्ति की देवी और श्रीकृष्ण की आंतरिक शक्ति के रूप में पूजी जाती हैं। उनका दिव्य प्रेम आध्यात्मिक प्रेम की एक मिसाल है। यदि श्रीकृष्ण लीला, माधुर्य और करुणा के अवतार हैं, तो राधा उस लीला का रस, उस माधुर्य की गहराई और उस करुणा की आत्मा हैं। इसीलिए भारतीय भक्ति परंपरा में कहा गया-राधे बिनु नहीं कृष्ण, कृष्ण बिनु नहीं राधे। राधा भारतीय संस्कृति में केवल एक स्त्री का नाम नहीं हैं, वे प्रेम की पराकाष्ठा और भक्ति की सर्वोच्च अभिव्यक्ति हैं। उनका प्रेम सांसारिक या देहाधारित नहीं, बल्कि आत्मा और परमात्मा का मिलन है। यह प्रेम स्वार्थ और अधिकार से परे है, यह प्रेम केवल समर्पण और तादात्म्य का है। राधा का जीवन त्याग और अनुराग का अद्भुत समन्वय है। उन्होंने कभी अपने लिए कुछ नहीं चाहा, उनका हर भाव, हर श्वास केवल श्रीकृष्ण में रमा रहा। यही कारण है कि भक्त कवियों ने राधा को 'भक्ति-रस की मूर्ति' और 'प्रेम की अधिष्ठात्री देवी' कहा। सूरदास ने लिखा-'प्रेम भया मनु भाव समाना, राधा तन मन कृष्ण बखाना।' अर्थात्, प्रेम ऐसा हो कि हृदय और आत्मा में केवल श्रीकृष्ण का ही वास हो जाए। निश्चित ही राधा और श्रीकृष्ण का संबंध, आत्मा और परमात्मा का अद्भुत एवं विलक्षण संवाद है। सामान्य दृष्टि से देखने पर राधा और श्रीकृष्ण का संबंध केवल प्रेमिका-प्रेमी का प्रतीत हो सकता है, लेकिन इसका वास्तविक अर्थ बहुत गहन है। यह संबंध सांसारिक नहीं, बल्कि आध्यात्मिक है। यह आत्मा और परमात्मा का शाश्वत संवाद इसलिये है कि इसमें किसी प्रकार का मोह, स्वार्थ या वासना नहीं है। राधा श्रीकृष्ण के व्यक्तित्व को पूर्णता प्रदान करती हैं। श्रीकृष्ण लीला के केंद्र हैं,

परंतु वह लीला राधा के बिना अधूरी है। इसीलिए भक्त परंपरा में श्रीकृष्ण का नाम लेने से पहले राधा का नाम लिया जाता है, ÷राधे-कृष्ण÷, ÷श्यामा-श्याम÷। यह क्रम अपने आप में गहरा दार्शनिक संदेश देता है कि परमात्मा तक पहुँचने का मार्ग राधा जैसे प्रेम और भक्ति से होकर जाता है। राधा केवल श्रीकृष्ण की प्रेयसी नहीं, बल्कि उनकी शक्ति और प्रेरणा हैं। गीता में श्रीकृष्ण ने प्रकृति के दो रूप बताए हैं-अपरा और परा। राधा को 'परा प्रकृति' का स्वरूप माना जाता है, जो जीवन को आध्यात्मिकता की ओर ले जाती है। वे श्रीकृष्ण की लीलाओं की आत्मा हैं, उनकी आराधना का आधार हैं। राधा के प्रेम में कोई अधिकार नहीं, केवल समर्पण है। उनका संदेश है कि सच्चा प्रेम पाने में नहीं, बल्कि देने में है। यही देने की भावना जीवन को ऊँचाई देती है। यह प्रेम केवल मनुष्य और मनुष्य के बीच संबंधों में ही नहीं, बल्कि मनुष्य और ईश्वर के संबंध में भी उतना ही प्रासंगिक है।

राधा की भक्ति को सर्वोच्च माना गया है। उनका प्रेम निष्काम है, केवल श्रीकृष्णमय है। उन्होंने अपने अस्तित्व को ही श्रीकृष्ण में विलीन कर दिया। यही कारण है कि चैतन्य महाप्रभु ने राधा की भक्ति को अपनाया और उसी रस में डूबकर कहा-'मैं राधा की भक्ति में श्रीकृष्ण को देखता हूँ और श्रीकृष्ण की भक्ति में राधा को।' सूरदास, रसखान, विद्यापति, मीराबाई-सभी भक्त कवियों ने राधा के माध्यम से ही प्रेम और भक्ति के गहनतम स्वरूप का चित्रण किया। मीराबाई ने जब कहा-÷मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई÷-तो उसमें राधा का ही भाव प्रतिध्वनित होता है। आज के समय में जब संबंधों में स्वार्थ, गणना और तात्कालिकता का समावेश बढ़ता जा रहा है, तब राधा का चरित्र हमारे लिए नई रोशनी देता है। सच्चा प्रेम वही है जिसमें समर्पण, विश्वास और त्याग हो। समकालीन जीवन में जहां परिवार और समाज टूटते जा रहे हैं, वहां राधा का संदेश और भी महत्वपूर्ण हो उठता है। उनका जीवन बताता है कि जब तक हम संबंधों को केवल लाभ-हानि की दृष्टि से देखते रहेंगे, तब तक उनमें स्थायित्व नहीं आएगा। स्थायित्व तभी आएगा जब उनमें राधा जैसा समर्पण होगा। भक्ति के स्तर पर भी राधा हमें प्रेरणा देती हैं। आज धर्म अक्सर कर्मकांड और बाहरी आडंबर तक सीमित होता जा रहा है। राधा हमें सिखाती हैं कि भक्ति हृदय की गहराई में होती है, जहां भक्त और भगवान का भेद मिट जाता है। जब हम राधा की तरह निष्काम होकर ईश्वर में समर्पित हो जाते हैं, तब जीवन की हर कठिनाई तुच्छ लगने लगती है और एक अद्भुत शांति प्राप्त होती है। राधा का जीवन हमें यह स्मरण कराता है कि मनुष्य का परम उद्देश्य केवल भौतिक सुख या उपलब्धि नहीं, बल्कि आत्मा और परमात्मा का मिलन है। वे हमें बताती हैं कि भक्ति केवल पूजा-पाठ नहीं, बल्कि हृदय की गहराई से ईश्वर के साथ तादात्म्य स्थापित करना है। आज जब मानवता संघर्ष, तनाव और अकेलेपन से गुजर रही है, राधा हमें सिखाती हैं कि सच्चा समाधान प्रेम और समर्पण में है। यदि हम राधा के जीवन से प्रेरणा लें, तो हमारे व्यक्तिगत संबंध, सामाजिक ताना-बाना और आध्यात्मिक जीवन सब में नई ऊर्जा और शांति का संचार हो सकता है। शास्त्रों में श्री राधा श्रीकृष्ण की शाश्वत शक्तिस्वरूपा एवम् प्राणों की अधिष्ठात्री देवी के रूप में वर्णित हैं अतः राधाजी की पूजा के बिना श्रीकृष्ण की पूजा अधूरी मानी गयी है। श्रीमद देवी भागवत में श्री नारायण ने नारदजी के प्रति 'श्री राधायै स्वाहा' षडाक्षर मंत्र की अति प्राचीन परंपरा तथा विलक्षण महिमा के वर्णन प्रसंग में श्री राधा पूजा की अनिवार्यता का निरूपण करते हुए कहा है कि श्री राधा की पूजा न की जाए तो मनुष्य श्रीकृष्ण की पूजा का अधिकार नहीं रखता। स्वयं भोलेनाथ ऋषि नारदजी के पूछने पर कहते हैं कि मैं तो श्रीराधा के रूप, लावण्य और गुण आदि का वर्णन करने मे अपने को असमर्थ पाता हूं।

बीस वर्ष पूर्व के फैसले का प्रचार उचित नहीं

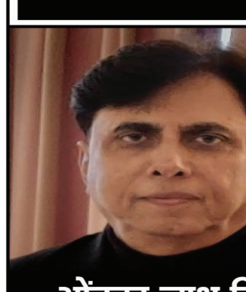

ओंकार नाथ सिंह

इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी के विरुद्ध गृह मंत्री अमित शाह ने एक बयान दिया जिसमे उन्होंने जस्टिस रेड्डी द्वारा बीस वर्ष पूर्व दिए गए फैसले की आलोचना करते हुए कहा कि यदि जस्टिस रेड्डी सलवा जुडूम का फैसला नहीं देते तो देश में वामपंथी उग्रवाद 2020 से पहले ही समाप्त हो जाता। गृह मंत्री के इस बयान की 18 पूर्व न्यायाधीशों ने आलोचना की। इस आलोचना में नौ सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश , तीन हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और शेष हाई कोर्ट के न्यायाधीश शामिल थे। उन्होंने कहा कि बीस वर्ष पूर्व के फैसले को भारत सरकार के गृह मंत्री द्वारा इस प्रकार प्रचार करना उचित नहीं है। वह फैसला डबल बेंच का था जिसने एक न्यायाधीश जस्टिस रेड्डी भी थे। समाचार पत्रों में जस्टिस रेड्डी का इंटरव्यू छपा है जिसमे उन्होंने विस्तार से उस फैसले के बारे में बताया है । उसके बाद दिनांक 26 अगस्त को 56 पूर्व न्यायाधीशों ने 18 पूर्व न्यायाधीशों को नसीहत दी कि पूर्व न्यायाधीशों को राजनीतिक बयान बाजी से बचना चाहिए । उन्होंने एक बयान जारी कर हर राजनीतिक घटना क्रम पर पूर्व न्यायाधीशों के एक समूह द्वारा जो बयान जारी किया वह उस पर अपनी आपत्ति जारी करने को बाध्य हैं। उन 56 पूर्व न्यायाधीशों ने कहा कि यह एक पैटर्न बन गया है कि जब कोई राजनीतिक घटनाक्रम होता है तो एक ही वर्ग से बयान आते हैं । यह बयान न्यायिक स्वतंत्रता की भाषा की आड़ में राजनीतिक तरफदारी होती है। इन 56 पूर्व न्यायाधीशों ने जो बयान जारी किया है उसको देख कर आश्चर्य होता है और स्पष्ट दिखता है कि सरकार के प्रयासों से यह बयान जारी हुआ है । इस पर हस्ताक्षर करने वाले जस्टिस गोगई भी हैं जो इस समय राज्य सभा के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य हैं । इन पूर्व न्यायाधीशों के पक्ष में पूर्व एटार्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने भी बयान दिया है जो भाजपा के शासनकाल में ही एटार्नी जनरल रह चुके हैं। इससे साफ़ दिखता है कि इस बयान को जारी करने में कहीं न कहीं सरकारी प्रयास है।आपको याद होगा कि जनवरी 2018 में सुप्रीम कोर्ट के चार वरिष्ठ जजों ने उस समय के मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा के विरुद्ध प्रेस कांफ्रेंस की थी जिसमें उन्होंने शीर्ष अदालत के प्रशासन में हो रही अनियमिताओं पर प्रश्न खड़े किए थे । उन्होंने प्रेस को बताया कि करीब दो महीने पहले उन लोगों ने एक पत्र मुख्य न्यायाधीश को लिखा और कहा कि जो कुछ भी हो रहा है वह सही नहीं है । जब उस पत्र पर कोई फैसला नहीं हुआ तब हम राष्ट्र के सामने अपनी बात लेकर आए हैं । उन्होंने कहा कि राष्ट्र को विचार करना है कि मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा पर महाभियोग चले या नहीं । परन्तु पत्र सार्वजनिक होने से पहले ही कोई समझौता हो गया । उन चार जजों के नाम इस प्रकार हैं- जस्टिस चेलमेश्वर, जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस मदन भीमराव लोकुर और जस्टिस कुरियन जोसफ़ । ध्यान देने की बात यह है कि उन चार जजों में जस्टिस गोगोई 56 पूर्व न्यायाधीशों में लिस्ट में सम्मिलित है और शेष तीन पूर्व न्यायाधीश जस्टिस जे चेलमेश्वर, जस्टिस मदन भीम राव लोकुर और जस्टिस कुरियन उन 18 जजों की सूची में शामिल हैं। जिन पूर्व न्यायाधीशों ने जिसमें जस्टिस गोगोई भी शामिल हैं,अठारह पूर्व न्यायाधीशों के बयान की आलोचना की वह अपने में आश्चर्य जनक है। जब सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान न्यायाधीश अपने मुख्य न्यायाधीश के विरुद्ध मानहानि तक जा सकते हैं तो पूर्व न्यायाधीशों के बयान की आलोचना करने का उन्हें किसने अधिकार दिया? माननीय पूर्व न्यायाधीशों ने शायद यह नहीं देखा होगा कि जब जब सरकार की ज्यादती होती है तो ऐसे कई मौके आए जिसमे देश की कार्यपालिका के रिटायर्ड वरिष्ठ अधिकारियों ने पूर्व न्यायाधीशों ने सरकार को पत्र द्वारा सरकार की कार्य प्रणाली पर गंभीर प्रश्न उठाए तो इसका यह मतलब तो नहीं बनता कि वह राजनीति कर रहे हैं। यह उनका दायित्व है कि जब कभी भी सरकार गलत कदम की तरफ़ बढ़े तो वह उन्हें सचेत करें। इसी प्रकार से उन पूर्व 18 न्यायाधीशों ने भी गृह मंत्री को सचेत किया कि प्रचार अभियान वैचारिक आधार पर गरिमा और शालीनता के साथ चलाया जा सकता है। यही लोकतंत्र की खूबसूरती होती है जो वर्तमान शासनकाल में नहीं दिख रही है। अभी जो उपराष्ट्रपति के पद का चुनाव होने जा रहा है उसमे चुनावी गणित सीधे सरकार के प्रत्याशी को विजय की तरफ़ ले जाते हुए दिख रहा है फिर इस प्रकार का बयान से ऐसा प्रतीत होता है कि कहीं न कहीं दाल में कुछ काला है। फ़िलहाल उपराष्ट्रपति का चुनाव शालीनता से होना चाहिए जिससे सरकार और विपक्ष के पास एक ऐसी खिड़की होनी चाहिए जिसमें से वह बच कर निकल सके इसलिय भाषा की मर्यादा को ध्यान में रखें और चुनाव प्रचार में दोनों ही पक्ष शालीनता दिखाएं क्यूंकि जीत तो एक की ही होगी और जीत के बाद जो भी उपराष्ट्रपति के पद पर सुशोभित होगा, तो दोनों पक्षों को ही उनकी आवश्यकता होगी ।

आज का राशि फल

मेषः- काफी दिनों से अवरोधित कोई हल होने के आसार बनेंगे। जीवन साथी के स्वास्य के प्रति सतर्कता अपेक्षित है। शिक्षा प्रतियोगिता की दिशा में किया गया प्रयत्न सार्थक होगा।

बृषभः- भावुकता व्यावहारिक जगत के अनुकूल चलने में बाधक होगी। अतः व्यवहार कुशल बने। भविष्य संबंधी कुछ चिंताएं मन पर प्रभावी होंगी। विद्यार्थी शिक्षा में लापरवाही न बरतें।

मिथुनः- मूल्यवान समय को व्यर्थ के कायरें में जाया न करें। नयी दिशा में सकारात्मक सोच अवश्य रंग लायेगी। सकारात्मक सोच को अपनाते हुए जीवन को सही दिशा की ओर केंद्रित करें और परिवार के अनुकूल चलें।

कर्कः- नये व्यावसायिक संबंध प्रगाढ़ होंगे। संवेदनशील शरीर ग्रहां की प्रतिकूलता से बीमार पड़ सकता है। महत्वपूर्ण कार्य की पूर्ति में असमर्थता जैसी स्थिति मन को निराश करेगी। पुरानी घटनाओं से मन को कष्ट संभव।

सिंहः- नयी घरेलू जिम्मेदारियों के पैदा होने से व्यय संभव। अच्छे कायरें से परिजनों के दिल में जगह बनायें। योजनाओं के फलीभूत होने से मन प्रसन्न होगा।

कन्याः- जीवनसाथी के स्वास्य के प्रति सचेत रहें। नये कायरें के क्रियान्वयन हेतु प्रयत्न तीव्र होगा। नये क्षेत्रों में प्रयास से लाभ संभव।

तुलाः- भविष्य को लेकर मन नकारात्मक आशंकाओं से प्रभावी रहेगा। प्रतिभाओं के बावजूद भी हीन भाव प्रतिभाओं के लाभ से वंचित करेगा। सुख-साधनों की लालसा बढ़ेगी। रोजगार में व्यस्तता रहेगी।

वृश्चिकः- रोजगार संबंधी कुछ नयी योजनाओं पर मन केंद्रित होगा। किसी कार्य में सफलता से उत्साह में वृद्धि होगी। कल्पनाओं में जीना छोड़ भौतिक जगत के अनुकूल चलने का प्रयत्न करें। भौतिक सुख में वृद्धि होगी।

धनुः- अपनी बातूनी कला का लाभ उठाएंगे। महत्वपूर्ण कार्य की पूर्ति में असमर्थता जैसी स्थिति मन को निराश करेगी।

मकरः- बीती बातों को सोचने के बजाय वर्तमान में जीने की चेष्ठा करें। जरूरत से ज्यादा बोलना व्यक्तित्व पर कुप्रभावी होगा। अतरू इसे सुधारें।

कुंभः- सब कुछ सामान्य होते हुए भी मन अरुचि का शिकार होगा। थोड़ा संयमी व धैर्यवान बने। भाग्य से प्राप्त सभी स्थितियों के मध्य समझौतावादी रवैया अपनायें। कुछ नई व्यस्तताएं सामने आएंगी। आलस्य कतई न करें।

मीनः- कुछ व्यासायिक कारणों से घर से दूर रहना पड़ सकता है। परिजनों की सुख-सुविधा के प्रति मन चिंतित होगा। मस्त-मौला मन ब्यर्थ के कायरे में समय जाया कर महत्वपूर्ण कार्य के प्रति लापरवाह के प्रति मन चिंतित होगा।

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का व्यवसायीकरण न हो

सार्वजनिक जीवन में शिष्ट आचरण या भद्र व्यवहार की मर्यादाओं का ध्यान रखना जरूरी माना जाता है। संयत व्यवहार और संयम के साथ बर्ताव पर भारतीय समाज में बल दिया जाता रहा है। इससे संवाद और सकारात्मक विचार-विनिमय के लिए अवसर निर्मित होता है। आज परिस्थितियाँ तेज़ी से बदल रही हैं और आधुनिकता के नाम पर उच्छृंखलता की तरफ कदम बढ़ने में देर नहीं लगाती है । संसद तक में इस तरह के दृश्य आए दिन दिख रहे हैं। यह सब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर होता है जो संविधान द्वारा प्रदत्त एक महत्वपूर्ण अधिकार है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि लोकतंत्र में नागरिकों की गरिमा की रक्षा के लिए इसका विशेष महत्व है और इसी हर कीमत पर रक्षा होनी ही चाहिए । विगत वर्षों में आई डिजिटल क्रांति ने संचार और संवाद का एक नया और चुनौती भरा वातावरण खड़ा कर दिया है। उसके बीच सोशल मीडिया की उभरती सर्वातिक्रामी भूमिका ने अभिव्यक्ति की शक्ति को अत्यंत प्रभावी बना दिया है। उसके साथ कई आर्थिक और नैतिक सवाल भी जुड़ गए हैं। अब तो मीडिया में प्रभावी लोगों (मीडिया इन्फ्लुएंसर्स) की एक नई विशिष्ट श्रेणी ही बन गई है। इनमें से अधिकांश लोग अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अपने नफे के लिए विधिवत व्यवसायीकरण करने में जुट गए हैं। दूसरे शब्दों में वे कमाई करने के लिए अभिव्यक्ति की खूब छूट ले रहे हैं। अपने कार्यक्रमों के दौरान उनके द्वारा की गई टिप्पणियां कई बार भारत के विविधतापूर्ण समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाती भी दिखती हैं। वे लोगों को अखर जाती हैं। उनके शिकारों में अकसर विकलांग, महिलाएं, बच्चे, वरिष्ठ नागरिक और अल्पसंख्यक वर्ग के लोग शामिल रहते हैं। खास बात यह है कि प्रभावशाली लोग जो कहते हैं वह आज के दौर में बड़ा मायने रखने लगा है। उनका दिया प्रत्यक्ष और परोक्ष संदेश एक पूरी पीढ़ी को प्रभावित करता दिख रहा है। ताजे घटनाक्रम में इससे जुड़े एक मामले में उच्चतम न्यायालय में न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति बागची की पीठ ने केंद्र सरकार से कहा है कि वह पॉडकास्ट जैसे ऑनलाइन शो सहित सोशल मीडिया पर आचरण को विनियमित करने के लिए राष्ट्रीय प्रसारकों और डिजिटल एसोसिएशन के परामर्श से व्यापक दिशा-निर्देश तैयार कर ले आए।

न्याय होता हुआ दिखेः तारीख़ पर तारीख़ की संस्कृति बदले

-ललित गर्ग-

देश के सर्वोच्च न्यायालय ने अपने 75 वर्ष का गरिमामय सफर पूरा किया है। यह केवल एक ऐतिहासिक पड़ाव नहीं, बल्कि भारतीय लोकतंत्र की आत्मा को परखने का अवसर भी है। न्यायपालिका ने इन आठ दशकों में अनेक युगांतरकारी फैसले दिये, जिन्होंने संविधान की मर्यादा और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा की। किंतु आज सबसे बड़ी चुनौती न्याय में विलंब की है। समय पर न्याय न मिले तो न्याय का वास्तविक अर्थ ही खो जाता है। शायद यही कारण है कि न्यायिक बिरादरी के आयोजनों में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्य न्यायाधीशों ने एक स्वर से कहा कि अब 'तारीख़ पर तारीख़' की संस्कृति को समाप्त करने का समय आ गया है। जिला न्यायपालिका के दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि त्वरित न्याय सुनिश्चित करने के लिये अदालतों में स्थगन की संस्कृति को बदलने के प्रयास करने की सख्त जरूरत है। उन्होंने स्वीकारा कि अदालतों में बड़ी संख्या में लंबित मामलों का होना हम सभी के लिये बड़ी चुनौती है सुप्रीम कोर्ट के 75 वर्ष पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि ये केवल एक संस्था की यात्रा नहीं है। ये यात्रा है भारत के संविधान और संवैधानिक मूल्यों की। ये यात्रा है एक लोकतंत्र के रूप में भारत के और परिपक्व होने की। भारत के लोगों ने सुप्रीम कोर्ट पर, हमारी न्यायपालिका पर विश्वास किया है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के ये 75 वर्ष 'मदर ऑफ डेमोक्रेसी' के रूप में भारत के गौरव को और बढ़ाते हैं। आजादी के अमृतकाल में 140 करोड़ देशवासियों का एक ही सपना है विकसित भारत, नया भारत बनने का। नया भारत, यानी सोच और संकल्प से एक आधुनिक भारत। हमारी न्यायपालिका इस विजन का एक मजबूत स्तम्भ है। भारत में लोकतंत्र और उदारवादी मूल्यों को मज़बूत करने में न्यायपालिका ने बेहद महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। संविधान का रखवाला, ग़रीबों के अधिकार एवं सरकार की ज्यादतियों के खिलाफ़ कमज़ोर समूहों का योग्य संरक्षक और करोड़ों नागरिकों के लिए आखरी उम्मीद वाला संस्थान है सुप्रीम कोर्ट। कुछ अपवादों को छोड़कर पिछले 75 वर्षों में ज्यादातर समय भारतीय न्यायपालिका संविधान की रक्षा

और क़ानून के शासन को बनाए रखने में सफल रही है। लेकिन भारतीय कानून व्यवस्था के सामने अनेक जटिल स्थितियां भी हैं, न्यायाधीशों की नियुक्ति, बढ़ते केसों की संख्या, जवाबदेही, भ्रष्टाचार एवं विलम्बित न्याय आदि। न्याय को लेकर अदालतों तक आम नागरिकों की पहुंच एवं खर्च के मुद्दों और इसी तरह की दूसरी चीज़ों के मामले में सुधार के बारे में न्यायपालिका की अपनी महत्वपूर्ण चिंताएं हैं। हमारे कानूनों की भावना है-नागरिक पहले, सम्मान पहले और न्याय पहले है इससे पहले जिला न्यायपालिका के राष्ट्रीय सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामलों में त्वरित न्याय की आवश्यकता पर बल दिया था ताकि महिलाओं में अपनी सुरक्षा को लेकर भरोसा बढ़ सके। निस्संदेह, हाल के वर्षों में महिलाओं के खिलाफ अपराधों में तेजी से वृद्धि हुई है, जिससे हमारे समाजशास्त्री और कानून लागू करवाने वाली विभिन्न एजेंसियां भी हैरान-परेशान हैं। महिलाओं के खिलाफ अपराधों बढ़ोतरी से पूरा समाज हिला हुआ है। कोलकाता मेडिकल कॉलेज की महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या की घटना ने यह स्पष्ट कर दिया कि अपराधियों के मन से कानून का भय लगभग समाप्त हो चुका है। यही कारण है कि अब न केवल कठोर कानून बल्कि त्वरित और निष्पक्ष न्याय की मांग बलवती हो रही है। आज न्यायपालिका के सामने सबसे बड़ी चुनौती है-न्याय में विलंब। जिला अदालतों से लेकर उच्चतम न्यायालय तक करोड़ों मामले लंबित हैं। केवल जिला अदालतों में ही साढ़े चार करोड़ से अधिक मामले अटके पड़े हैं। यह स्थिति लोकतंत्र की आत्मा को आहत करती है, क्योंकि न्याय में विलंब, न्याय के इनकार के समान है। दरअसल, लंबित मामलों के पीछे कई कारण हैं- न्यायाधीशों की अपर्याप्त संख्या, अदालती प्रक्रियाओं की जटिलता, अनावश्यक स्थगन, वकीलों द्वारा मुकदमों को खींचना और पुलिस-प्रशासन की लापरवाही। यही वजह है कि अपराधियों के मन से कानून का भय कम होता जा रहा है और आम नागरिक का भरोसा डगमगाने लगता है। भारतीय न्यायिक व्यवस्था की रीढ़ जिला एवं स्थानीय अदालतें हैं। यदि इन स्तरों पर शीघ्र और सस्ता न्याय नहीं मिलेगा, तो सुप्रीम कोर्ट की उपलब्धियां अधूरी मानी जाएंगी। सर्वोच्च न्यायालय समय-समय पर स्वतः संज्ञान लेकर राहत देता रहा है-जैसे हाल ही में डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय प्रोटोकॉल बनवाने की पहल। किंतु जिला स्तर पर ऐसी सजगता और सक्रियता नहीं दिखाई देती। इसलिए सुधार की असली शुरुआत निचले स्तर से ही करनी होगी। भारतीय न्याय प्रणाली की विसंगतियां और सुधार की राह जटिल है, लेकिन असंभव नहीं है। दृढ़ संकल्प एवं कार्ययोजना के साथ आगे बढ़े तो आजादी के अमृतकाल में हम न्याय प्रणाली को युगांतरकारी मोड़ दे सकते हैं। देश में जनसंख्या के अनुपात में न्यायाधीशों की संख्या बहुत कम है। तत्काल नियुक्तियों और प्रशिक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए। ई-कोर्ट, ऑनलाइन सुनवाई, डिजिटल साक्ष्य प्रबंधन जैसे कदम न्याय प्रक्रिया को गति दे सकते हैं। अनावश्यक स्थगन पर अंकुश जरूरी है। क्योंकि स्थगन देने की परंपरा अपराधियों और वकीलों के लिये हथियार बन चुकी है। इस पर कड़ा नियंत्रण जरूरी है। पुलिस व जांच एजेंसियों को दायित्वशील एवं जिम्मेदार बनाना होगा। क्योंकि पुख्ता सबूतों और चार्जशीट समय पर दाखिल करने से ही मामलों में शीघ्र निर्णय संभव है। अदालतों के साथ-साथ वकीलों और पुलिस पर भी जवाबदेही तय करनी होगी। महिलाओं, बच्चों और संवेदनशील मामलों के लिये विशेष फास्ट-ट्रैक अदालतों को और मजबूती देनी होगी।

विकसित भारत के लिए एक्शन में सीएम योगी कहा- हर क्षेत्र को चिह्नित करके काम करना जरूरी

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को कहा कि 2047

तक विकसित भारत बनाने का सपना साकार करने के लिये देश के हर क्षेत्र को चिह्नित करके काम करना होगा। मुख्यमंत्री ने आईआईटी-कानपुर के उद्योगकृअकादमिक जुड़ाव कार्यक्रम 'समन्वय' में हिस्सा लेते हुए अपने संबोधन में विकसित भारत और अर्थव्यवस्था समेत विभिन्न विषयों पर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि विकसित भारत केवल विकसित नहीं होगा बल्कि वह आत्मनिर्भर भी होगा और जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आत्मनिर्भरता होगी। योगी सरकार की नौकरियां आदित्यनाथ ने कहा कि विकसित भारत के लिए हर एक क्षेत्र को चिन्हित करके उस पर काम करना होगा। उन्होंने कहा, पिछले 11 वर्षों में आपने बदलते हुए भारत को देखा है। यह बदलता हुआ भारत जो आज फिर से दुनिया की सबसे तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था में से एक है, आज दुनिया की चैथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और अगले दो वर्ष में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। तीसरी से दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने में युवाओं का योगदान होना है और हमारे लिए वह समय विकसित भारत का होगा। आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की पूर्ववर्ती सरकारों पर परोक्ष रूप से निशाना साधते हुए कहा कि वर्ष 2017 में भाजपा के सत्ता में आने से पहले उत्तर प्रदेश में एक निराशाजनक वातावरण था और देश में यह धारणा बन चुकी थी कि उत्तर प्रदेश सुधरने वाला नहीं है। उन्होंने कहा कि उन्हें यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि पिछले आठ वर्ष में उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के निवासियों के साथ मिलकर जो प्रयास प्रारंभ किये, उनका परिणाम है कि आज उत्तर प्रदेश देश की नंबर दो अर्थव्यवस्था वाला राज्य बन चुका है। उन्होंने इस अवसर पर आईआईटी कानपुर द्वारा आयोजित समन्वय कार्यक्रम की सराहना करते हुए कहा कि कार्यक्रम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और सस्टेनेबिलिटी नामक तीन महत्वपूर्ण विषयों पर अलग-अलग सत्र होंगे और उन सभी मुद्दों पर चर्चा होगी जिन्हें लेकर आज एक सामान्य नागरिक, समाज, देश और दुनिया भी चिंतित है। उन्होंने कहा कि इससे लाभान्वित होकर वे अपने आप को आगे बढ़ाना चाहेंगे। मुख्यमंत्री ने आईआईटी-कानपुर और उत्तर प्रदेश सरकार के बीच तालमेल का जिक्र करते हुए कहा कि कोविड महामारी के दौरान विभिन्न निदानात्मक आकलनों के जरिये सरकार की मदद करने वाले इस संस्थान से डिफेंस कॉरिडोर परियोजना में भी सहयोग मिल रहा है।

कोर्ट ने राजनीतिक दलों से मांगा 10 सालों के जातीय रैलियों का रिकॉर्ड, केंद्र और राज्य सरकार से किया जवाब तलब

लखनऊ। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने जातीय रैलियों

पर रोक के मामले में केंद्र व राज्य सरकार से पूछा है कि दोनों सरकारें जातीय रैलियां रोकने को क्या उपाय कर रही हैं। अदालत ने दोनों को जवाब दाखिल करने का समय देकर अगली सुनवाई अक्तूबर के दूसरे सप्ताह में नियत की है। पहले कोर्ट ने केंद्र सरकार को मामले में जवाब पेश करने का मौका दिया था। साथ ही कोर्ट ने याची को भी पिछले 10 साल में राजनीतिक दलों द्वारा आयोजित की गई जातीय रैलियों का ब्योरा नए हलफनामे पर दाखिल करने को कहा था। न्यायमूर्ति राजन रॉय और न्यायमूर्ति मंजीव शुक्ल की खंडपीठ ने बुधवार को यह आदेश स्थानीय अधिवक्ता मोतीलाल यादव की जनहित याचिका पर दिया। पहले, इस मामले में कोर्ट ने पक्षकारों केंद्र व राज्य सरकार समेत केंद्रीय निर्वाचन आयोग एवं चार राजनीतिक दलों कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा), समाजवादी पार्टी (सपा) और बहुजन समाज पार्टी (बसपा) से जवाब मांगा था। याचिकाकर्ता ने यह याचिका वर्ष 2013 में दायर की थी। उसका कहना था कि उत्तर प्रदेश में जातियों पर आधारित राजनीतिक रैलियों की बाढ़ आ गयी है। सियासी दल ब्राह्मण रैली, क्षत्रिय रैली, वैश्य सम्मेलन आदि नाम देकर अंधाधुंध जातीय रैलियां कर रहे हैं, जिन पर रोक लगाई जानी चाहिए। योगी सरकार की नौकरियां दरअसल, 11 जुलाई 2013 को कोर्ट ने को एक अहम आदेश में पूरे उत्तर प्रदेश में जातियों के आधार पर की जा रही राजनीतिक दलों की रैलियों पर तत्काल रोक लगा दी थी। साथ ही इन पक्षकारों को नोटिस जारी की थी। याची का तर्क था कि इससे सामाजिक एकता और समरसता को जहां नुकसान हो रहा है वहीं, ऐसी जातीय रैलियां तथा सम्मेलन समाज में लोगों के बीच जहर घोलने का काम कर रहे हैं, जो संविधान की मंशा के खिलाफ है।

खाद के लिए सपाइयों ने घेरा कलेक्ट्रेट सड़क पर लेट कर प्रदर्शन किया

लखनऊ। राजधानी लखनऊ में बुधवार को समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने

जिलाधिकारी कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन किया। सर पर यूरिया की बोरी रखकर और शरीर पर खाद की बोरी पहनकर 2 घण्टे तक जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर नारेबाजी किया। प्रदर्शन कर रहे सपा कार्यकर्ताओं ने वोट चोर गद्दी छोड़ यूरिया खाद चोर गद्दी छोड़ के नारे लगाए। प्रदर्शन में समाजवादी पार्टी के मोहनलालगंज से सांसद आरके चैधरी, नेशनल स्पोक पर्सन जूही सिंह समेत बड़ी संख्या में यूथ बिर्गेड, महिला सभा और युवा मोर्चा के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने हंगामा और नारेबाजी किया। प्रदर्शन के दौरान खाद की बोरी ओढ़ कर कार्यकर्ता सड़क पर लेट गए हंगामा और नारेबाजी करने लगे। सपा की राष्ट्रीय प्रवक्ता जूही सिंह ने कहा कि यह सरकार किसान विरोधी है। किसानों को खाद मिल नहीं रही है यूरिया की इतनी किल्लत है कि किसान सुबह-शाम सड़कों पर संघर्ष कर रहा है। जब तक जिलाधिकारी हमारा ज्ञापन लेकर कार्रवाई का आश्वासन नहीं देंगे हम प्रदर्शन करते रहेंगे। किसने की समस्याओं का समाधान नहीं होगा तो हम लोग सड़कों पर बारबार उतरेंगे और घेराव करते रहेंगे। जूही सिंह ने कहा कि किसानों को यूरिया नहीं मिल रहा है। वह खुदकुशी करने पर मजबूर है। यूपी में किसानों की जमीन बिक रही है फसलों का मूल्य मिल नहीं रहा है। यह सरकार किसानों के मुद्दे को हल करने का और गद्दी छोड़ने का काम करे। सिंचाई , दवाई सब महंगी हो गई है किसान का जीवन गुजारना मुश्किल होता जा रहा है। सरकार किसानों को गुमराह करने का काम कर रही है केंद्र और राज्य में भाजपा है बताएं कि इन्होंने किसानों के लिए क्या किया और उसके मुद्दों का कैसे समाधान करेगी। प्रदर्शन कर रहे शिव शंकर ने कहा आज हम लोग प्रदर्शन करने पर मजबूर है। जब मुलायम सिंह मुख्यमंत्री थे तो यूरिया खाद की बोरी 50 किलो की होती थी और अब घाट के 40 किलो की हो गई है। यह लोग खाद चोरी कर रहे हैं और ऊपर से दाम बढ़ा रहे हैं जिसकी वजह से खाद मिल नहीं रही है। आबकारी विभाग 24 घंटे दारु बेच रहा है ऑनलाइन सुविधा दे रहा है। यूरिया खाद मात्र दो महीना बिकता है वह भी पूरा नहीं पड़ रहा है और कालाबाजारी और चोरी हो रही है। सरकार का वादा था कि आज दुगनी होगी मगर किसने की आया आधी हो गई है।

ब्लास्ट से पानी टंकी में दरार बेहटा इलाके में 3 दिन में तीसरा धमाका

लखनऊ। गुडंबा थाना क्षेत्र के बेहटा गांव में मंगलवार देर रात फिर यानी 72

घंटे में तीसरा धमाका हुआ। इस गांव में इससे पहले भी दो बार विस्फोट हो चुके हैं, जिनमें एक दंपती और एक गाय की मौत हो चुकी है। ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। पुलिस की लापरवाही पर सवाल उठने लगे हैं। पुलिस और बम स्क्वायड ने सोमवार और मंगलवार को बेहटा गांव और आसपास छापेमारी की थी। इस दौरान करीब 30 क्विंटल विस्फोटक बरामद किया था। उसे 15-15 फीट के गहरे गड्ढे में नष्ट कर दिया था। उन्हीं गड्ढों में मंगलवार रात अचानक धमाका हो गया। इससे पास में स्थित जल जीवन मिशन के तहत बनी पानी की टंकी में दरार आ गई। डर की वजह से लोग रातभर सो नहीं पाए। लोगों ने बताया कि पुलिस ने विस्फोटक नष्ट करने में लापरवाही बरती। विस्फोटक को गड्ढे में दबाने के बाद उसमें पानी नहीं भरा। इसकी वजह से उसमें ब्लॉस्ट हो गया। सोमवार और मंगलवार को पुलिस टीम ने बेहटा में छापेमारी की। अली अहमद उर्फ टिनू के गोदाम से 15 बोरी में देसी सुतली बम जिसका वजन करीब 620 किलोग्राम खुली बारूद करीब 30 किलो, सुतली 1 बोरी, बुरादा 5 बोरी बरामद हुआ। घपलू के पास से देसी पटाखे 6 बोरी, बारूद खुली करीब 240 किलोग्राम, पटाखा बनाने की सामग्री 12 बोरी, पटाखे के खोखे 4 बोरी विस्फोटक पदार्थ बरामद हुआ। शेरू उर्फ बशीर के गोदाम के अन्दर करीब 320 किलोग्राम बारूद, खुली बोरी में 800 किलोग्राम, देसी पटाखे बने हुए, एक डिब्बे में करीब 20 किलोग्राम बारूद 2 बोरी पटाखे के खोखे व 4 बोरी बुरादा बरामद हुआ। नसीम के खेतों में बने गोदाम से देसी पटाखे बने हुए 10 बोरी में, बारूद 2 बोरी में करीब 80 किलोग्राम बड़े बन्द ड्रम में बारूद करीब 50 किलोग्राम बरामद हुआ। अफजल के खेत में बने गोदाम से पटाखा बनाने की सामग्री बुरादा 10 बोरी, पटाखा बनाने के खोखे कागज के 8 बोरी, बरामद हुआ। अली अकबर गोदाम में विभिन्न प्रकार के देसी पटाखे 18 बोरी में जिनका वजन करीब 700 किलोग्राम, एक ड्रम में बारुद खुला हुआ। करीब 50 किलोग्राम 5 बोरी खुली बारूद करीब 250 किलोग्राम बरामद हुआ।

महिला आयोग अध्यक्ष ने अस्पतालों का निरीक्षण किया

लखनऊ। उत्तर प्रदेश महिला आयोग की अध्यक्ष बबिता चैहान ने बुधवार को लखनऊ के महिला अस्पतालों का निरीक्षण किया। पहले वो अवंति बाई महिला अस्पताल गईं। इसके बाद केजीएमयू के क्वीनमैरी अस्पताल में प्रसूताओं को मिलने वाली सुविधाओं का जायजा लेने पहुंचीं। इस दौरान उन्होंने दोनों अस्पतालों में मरीजों की सहायता के लिए अपने सुझाव भी दिए। सुबह साढ़े 11 बजे के करीब महिला आयोग की अध्यक्ष अवंति बाई हॉस्पिटल पहुंचीं। थोड़ी देर बाद उनका निरीक्षण शुरू हुआ। ओपीडी से लेकर ऑपरेशन थिएटर को उन्होंने देखा। यहां के मरीजों से भी मिली। इसके लेबर रूम और किचन की सुविधाओं को भी परखा। वॉर्ड में एडमिट मरीजों से उन्होंने पूछा कि आज सुबह से कोई डॉक्टर राउंड लेने नहीं आया क्या? इसके जवाब में महिला मरीजों ने कहा कि नहीं मैडम, राउंड हो गया। डॉक्टर आई थीं। इससे पहले ओपीडी में बैठी प्रसूताओं से भी उन्होंने पूछा कि कितने देर हुए यहां बैठी हैं, जिसके जवाब में मरीजों ने बताया कि अभी कुछ देर पहले आए हैं। कोई मरीज उन्हें परेशानी बताता नहीं दिखा।

पुलिस की पिटाई से घायल छात्रों से मिले केशव मौर्य,किसी का हाथ-पैर तोड़ना कतई स्वीकार नहीं

लखनऊ। पुलिस की पिटाई से घायल ।ठटच् छात्रों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य केजीएमयू में मिले। केजीएमयू के फेज-2 में 9 छात्र भर्ती हैं। यहां उनका

हालचाल जानने के बाद केशव मौर्य ने मीडिया से कहा कि पुलिस ने छात्रों के साथ बहुत गलत किया। बर्बरता पूर्वक लाठीचार्ज कर किसी का हाथ-पैर तोड़ देना कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता। पुलिस की कार्रवाई बेहद बर्बर है। दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हुई है। पुलिस की शांति व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी है। कहा एबीवीपी बेहद सांस्कारिक संगठन है। वह अपनी जिम्मेदारी समझता है। पुलिस को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। संगठन के छात्र यूनिवर्सिटी में अपनी वैध मांगों की बात रख रहे थे। उन पर इस तरह की कार्रवाई बर्दाश्त नहीं है। पुलिस की कार्रवाई गैर जिम्मेदाराना है। बहुत गलत किया। उसकी जांच भी होगी और कार्रवाई भी की जाएगी। एबीवीपी सांस्कारिक संगठन है। अपनी जिम्मेदारी समझता है। शिक्षा के हित में जब कहीं कोई कमी आती थी, तो आंदोलन होते थे। लेकिन, छात्रों के साथ इस तरह का व्यवहार कभी नहीं हुआ, जिस तरीके से ।ठटच् के छात्रों को निशाना बनाया गया। घटना को लेकर सपा और अन्य संगठनों से मिल रहे समर्थन के सवाल पर उन्होंने कहा कि इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते।

बुद्धा पार्क में शिवालय निर्माण योजना रद्द मायावती ने योगी सरकार के फैसले का किया स्वागत

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के कानपुर स्थित बुद्धा पार्क में प्रस्तावित शिवालय पार्क

के निर्माण को लेकर उठा विवाद अब शांत होता नजर आ रहा है। राज्य सरकार द्वारा इस योजना को रद्द किए जाने पर बहुजन समाज पार्टी (बसपा) प्रमुख मायावती ने सरकार का आभार जताया है। हाल के दिनों में खबर आई थी कि कानपुर के कल्याणपुर इलाके में स्थित प्रसिद्ध बुद्धा पार्क में शिवालय पार्क विकसित करने तथा 12 ज्योतिर्लिंगों की प्रतिकृतियाँ स्थापित करने का प्रस्ताव रखा गया था। यह कदम बौद्ध समुदाय और डॉ. भीमराव अंबेडकर के अनुयायियों के विरोध के चलते विवाद का केंद्र बन गया था। बसपा सुप्रीमो मायावती ने इस निर्णय को सामाजिक सौहार्द बनाए रखने की दिशा में सही कदमष् बताया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर बयान जारी कर कहा, बुद्धा पार्क बौद्ध धर्म और अम्बेडकरवादियों के लिए आस्था का केंद्र है। वहां किसी अन्य धर्म का पूजा स्थल प्रस्तावित करना अनुचित था। मैं इस प्रस्ताव को रद्द करने के लिए सरकार का धन्यवाद करती हूं। उन्होंने यह भी कहा कि ऐसे प्रयास संविधान में निहित धर्मनिरपेक्षता की भावना के विपरीत हैं और समाज में अशांति का कारण बन सकते हैं। बुद्धा पार्क प्रकरण पर केवल बसपा ही नहीं, बल्कि भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने भी विरोध दर्ज कराया था। दोनों नेताओं ने इसे बौद्ध अनुयायियों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ बताते हुए सरकार से निर्णय वापस लेने की मांग की थी। मायावती ने दोहराया कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, जहां सभी धर्मों के लोगों को समान अधिकार प्राप्त हैं। उन्होंने सरकार से आग्रह किया कि भविष्य में इस प्रकार के विवादास्पद निर्णयों से बचने के लिए कड़े कदम उठाए जाएं और सामाजिक सौहार्द को प्राथमिकता दी जाए।

छात्रों को न्याय दिलाने को लेकर समाजवादी छात्र सभा का जोरदार प्रदर्शन

लखनऊ। राजधानी में समाजवादी छात्र सभा ने आज जोरदार प्रदर्शन किया। सपाइयों ने राजभवन का घेराव किया। पुलिस की गाड़ी पर चढ़ गए। प्रदेश सरकार और पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों की पुलिस से तीखी नोकझोंक हुई। पुलिस उन्हें घसीटकर और टांगकर गाड़ियों में बैठाया। उसके बाद ईको गार्डन धरना स्थल ले गई। सपाई राम स्वरूप यूनिवर्सिटी में प्रदर्शन के दौरान छात्रों और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं पर हुए लाठी चार्ज का विरोध कर रहे थे। सपाइयों ने कहा कि इस मामले में वे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के साथ हैं। छात्रों के साथ किसी भी कीमत पर अन्याय नहीं होने देंगे। उन्हें न्याय दिलाने के लिए हर स्तर पर लड़ाई लड़ेंगे। जरूरत पड़ी तो दिल्ली तक जाएंगे। प्रदर्शन कर रहे अमरेंद्र ने कहा कि हम लोग रामस्वरूप यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले छात्रों के समर्थन में उतरे हैं। रामस्वरूप यूनिवर्सिटी को स्स्ठ की डिग्री देने की मान्यता नहीं है, फिर भी वह लोग फर्जी डिग्री दे रहे हैं। छात्रों के साथ अन्याय और अत्याचार कर रहे हैं। छात्रों के ऊपर अनावश्यक 500 का जुर्माना लगा रहे हैं। एबीवीपी के छात्रों पर जमकर लाठी बरसाई गई, हम लोग उसके खिलाफ हैं। पुलिस प्रशासन को आगे करके छात्रों के साथ अन्याय किया गया है। हम छात्राओं को न्याय दिलाने के लिए मैदान में उतरे हैं। प्रदर्शन कर रहे तुषार ने कहा कि छात्रों के साथ अन्याय हो रहा है। जरूरत पड़ेगी तो हम लोग दिल्ली तक यह लड़ाई लड़ेंगे। छात्रों के साथ अन्याय नहीं सहेंगे। योगी सरकार पूरी तरीके से विफल हो चुकी है। बेरोजगार युवाओं को नौकरी नहीं दे पा रही है। अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए छात्रों के ऊपर लाठी बरसाई जा रही है। हम समाजवादी लोग प्रत्येक छात्र संगठन के साथ खड़े हैं, जहां भी पुलिस बर्बरता और अन्याय करेगी हम लोग लोग उस के खिलाफ लड़ाई लड़ते हुए नजर आएंगे।

भूटान के प्रधानमंत्री कल आयेंगे अयोध्या, करेंगे रामलला के दर्शन

लखनऊ। भूटान के प्रधानमंत्री दासो शेरिंग टोबगे 5 सितंबर को भारत के दौरे पर आ रहे हैं, उनकी ये भारत यात्रा काफी महत्पूर्ण मानी जा रही है। वो अयोध्या का दौरा करेंगे।अयोध्या में भूटान के पीएम राम जन्मभूमि में पूजा-अर्चना करेंगे। प्रधानमंत्री दासो शेरिंग टोबगे 5 सितंबर को सुबह लगभग 9रू30 बजे महर्षि वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचेंगे।उनकी पत्नी ओम ताशिम डोमा भी उनके साथ अयोध्या आएंगी।अयोध्या में सूडान के पीएम भगवान श्रीरामलला, हनुमानगढ़ी और अयोध्या के अन्य प्रमुख मंदिरों में दर्शन और पूजन-अर्चना करेंगे. जिसके लिए जिला प्रशासन विशेष तैयारियों में जुट गया है। भूटान के प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत रेड कार्पेट पर किया जाएगा।इस मौके पर कई मंत्री मौजूद रहेंगे।डीएम निखिल टीकाराम के मुताबिक दासो शेरिंग टोबगे के लिए दिन में खास भोज आयोजित किया जाएगा।करीब 1रू30 बजे उनका अयोध्या से प्रस्थान का कार्यक्रम है।वे अयोध्या में महत्वपूर्ण धार्मिक स्थानों पर दर्शन और पूजा पाठ करने के बाद अयोध्या एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए निकल जाएंगे।दिल्ली में वो विदेश मंत्री एस. जयशंकर के साथ मुलाकात करेंगे।3 से 6 सितंबर तक भूटान के प्रधानमंत्री दासो शेरिंग टोबगे अपनी पत्नी ओम ताशिम डोमा के साथ भारत की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे।उनका भारत दौरा 6 सितंबर को खत्म हो जाएगा।अयोध्या में उनके आने को लेकर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की जा रही है।दासो शेरिंग टोबगे इससे पहले भी भारत आ चुके हैं। वे 21 और 22 फरवरी को भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए थे। स्कूल ऑफ लीडरशिप के पहले लीडरशिप कॉन्क्लेव में भाग लिया था। पिछली बार जब सूडान के पीएम भारत आए थे तब उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री मोदी से हुई थी।विदेश मंत्रालय के बयान के अनुसार इस तरह की लगातार यात्राएं सूडान के भारत से मजबूत होते रिशते और सहयोग को दर्शाता है।

केतकी का घर सपाइयों ने घेरा, बेटी बोली-मां फाड़ देगी,टोटियां लेकर पहुंचीं थी सपा कार्यकर्ता

लखनऊ। राजधानी में सपा की महिला कार्यकर्ताओं ने भाजपा विधायक केतकी सिंह का घर घेर लिया। हाथ में टोटियां लेकर विरोध प्रदर्शन करने लगीं। महिलाओं ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर की गई टिप्पणी के विरोध में केतकी सिंह मुर्दाबाद के नारे लगाए। हंगामा बढ़ता देख महिला पुलिस मौके पर पहुंची। सपा कार्यकर्ताओं की पुलिस से नोकझोंक हो गई। 45 मिनट चले हंगामे के बाद पुलिस ने महिला कार्यकर्ताओं को टांगकर बस में बैठाया। उन्हें ईको गार्डन धरना स्थल ले गई। बलिया के बांसडीह से विधायक केतकी सिंह ने मंगलवार को अखिलेश यादव पर कहा था कि पहले टोटियां वापस करें। फिर सरकार से सवाल करें। भाजपा विधायक केतकी सिंह की नाबालिग बेटी ने कहा मेरी मां बलिया में हैं।

विशेष समुदाय द्वारा पत्थरबाजी आरोपियों को 48 घंटे बाद भी पुलिस नहीं कर सकी गिरफ्तार,

आलमबाग। पीजीआई थाना क्षेत्र के रथिन्द्र नगर तेलीबाग में दो दिन पूर्व देररात्रि पड़ोस में रह रहे विशेष समुदाय के परिवार ने एक परिवार के घर पर विवाद चलते पथराव किया था जिसकी सूचना पीड़िता ने कंट्रोल पुलिस समेत स्थानीय पुलिस को दी थी,पीड़िता की नामजद शिकायत पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया था लेकिन आरोपियों को गिरफ्तार करने में विफल रही।पीड़िता ने पुलिस की कार्यवाही से असंतुष्ट हो पुलिस आयुक्त से लिखित शिकायत की है।रायबरेली रोड तेलीबाग रथिन्द्र नगर निवासिनी पूजा तिवारी की माने तो दो दिन पूर्व बीते रविवार रात्रि करीब 12 बजे उनके पड़ोस के सामने रहने वाले मलखान, सुल्तान, साजिद, साबिर, गुलफ्शा खातून व इनकी भाभी समेत आधा दर्जन लोग उसके घर पर चढ़ाई

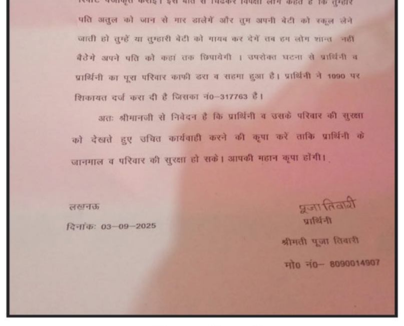

महोदय,

सादर अवगत कराना है कि श्रीमती पूजा तिवारी पत्नी अतुल तिवारी निवासिनी– 592ज/85 रथीन्द्र नगर, तेलीबाग, लखनऊ की है। प्रार्थिनी के घर से रोड पर आने का एक ही रास्ता है। प्रार्थिनी जब भी घर से निकलती है तो गली में रहने वाले मलखान, सुल्तान, साजिद, साबिर, गुलफशा खातून व मलखान की भाभी ये सभी लोग गन्दे–गन्दे शब्द बोलते हैं और गन्दी–2 हरकते भी करते हैं तब प्रार्थिनी ने थाना पी0जी0आई0 पर एक प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत कराई। इस बात से चिढ़कर विपक्षी लोग कहते हैं कि तुम्हारे पति अतुल को जान से मार डालेगें और तुम अपनी बेटी को स्कूल लेने जाती हो तुम्हें या तुम्हारी बेटी को गायब कर देगें तब हम लोग शान्त नहीं बैठेगे अपने पति को कहां तक छिपायेगी । उपरोक्त घटना से प्रार्थिनी व प्रार्थिनी का पूरा परिवार काफी डरा व सहमा हुआ है। प्रार्थिनी ने 1090 पर शिकायत दर्ज करा दी है जिसका नं0–317763 है।

अतः श्रीमानजी से निवेदन है कि प्रार्थिनी व उसके परिवार की सुरक्षा को देखते हुए उचित कार्यवाही करने की कृपा करें ताकि प्रार्थिनी के जानमाल व परिवार की सुरक्षा हो सके। आपकी महान कृपा होगी।

लखनऊ

दिनांक: 03–09–2025

पूजा तिवारी
प्रार्थिनी
श्रीमती पूजा तिवारी
मो0 नं0– 8090014907

कर पथराव बाजी करने लगे इस पथराव से उनका पूरा परिवार दहशत में आ गया था इस घटना की सीसी फुटेज उनके घर में लगे सीसी कैमरे में भी कैद हुआ था सूचना पाकर मौके पर पुलिस भी आई थी लेकिन एक भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर सकी। पीड़िता का आरोप है उसकी लिखित शिकायत पर पीजीआई पुलिस घटना के 24 घंटे बाद मंगलवार को मुकदमा तो दर्ज कर लिया लेकिन आरोपियों की गिरफ्तारी न होने से उनके हौसले बुलंद है और जब भी वह घर के बाहर निकलते है तो आरोपित छींटाकशी और धमकी भरे लब्ज़ बोल तानेबाजी करते है ।पुलिस की इस कार्यवाही से असंतुष्ट पीड़िता ने बुधवार को पुलिस कमिश्नर कार्यालय में प्रस्तुत हो पुलिस आयुक्त से शिकायत की है।

सांसद खेल स्पर्धा के सॉफ्ट लॉन्चिंग के तहत आज तीसरे और दिन, साइकिल रैली का आयोजन किया गया

एमएम खान उर्फ फिरोज मंडल ब्यूरो गोरखपुर

इसका उद्घाटन स्थानीय महिला जिला चिकित्सालय से जिलाधिकारी श्री संतोष कुमार शर्मा ने साइकिल रैली को झंडा दिखाकर किया। रैली का आयोजन युवा कल्याण विभाग और क्रीड़ा विभाग के संयुक्त तत्वावधान में कुल 48 साइकिलचालक बच्चों ने प्रतिभाग किया। ये रैली स्थानीय शाहू जी महाराज स्पोर्ट्स स्टेडियम पर समाप्त हुआ। इसमें सबसे पहले पहुंचने वाले 10 साइकिल चालकों को पुरस्कृत भी किया गया। साइकिल रैली के बाद खेल विभाग के तरफ से साइकिल रेस भी आयोजित किया गया और उसमें प्रथम द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले साइकिल चालकों को भी पुरस्कृत किया गया। 29 अगस्त को खेल दिवस के अवसर पर सांसद खेल स्पर्धा के लॉन्चिंग के बाद से खिलाड़ियों में उत्साह देखा जा रहा है और उनकी तैयारी में तेजी आई है। 21 सितंबर से इसके फॉर्म सभी स्थान पर उपलब्ध कराया जाना है। इस अवसर पर अवसर पर अपर जिलाधिकारी डा प्रशांत कुमार, युवा कल्याण अधिकारी वैभव कुमार सिंह, ओलंपिक संघ के अध्यक्ष विंध्यवासिनी सिंह एवं अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे।

आगामी पर्वों के दृष्टिगत डीएम और एसपी ने कलेक्ट्रेट सभागार में विभिन्न समुदायों के साथ पीस कमेटी की बैठक की गई

एम एम खान उर्फ फिरोज मंडल ब्यूरो गोरखपुर

बैठक को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी महोदय ने कहा कि सभी लोग आगामी त्योहारों में शासन द्वारा निर्धारित गाइडलाइंस का अनुपालन सुनिश्चित करें। जुलूस से पहले निर्धारित शर्तों के अनुसार पूर्वानुमति अवश्य ले लें। जुलूस/कार्यक्रम में कोई भी अप्रिय स्थिति होने पर पूरी जिम्मेदारी आयोजकों की होगी। जुलूस में मानक के अनुसार डीजे की आवाज रखें और जुलूस में झंडा लगाने के लिए धातु का इस्तेमाल न करें। जिलाधिकारी महोदय ने अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि सड़कों पर अनावश्यक झंडे/पोस्टर/बैनर को अभियान चलाकर हटवा लें। विद्युत विभाग को जुलूस मार्गों पर विद्युत खंबो और विद्युत तारों का सर्वे कर उनकी मरम्मत करवा लें। कहीं पर भी तार निर्धारित सीमा से नीचे लटकते न मिलें। उन्होंने सभी एसडीएम को सीओ के साथ संवेदनशील क्षेत्रों के स्थलीय निरीक्षण का निर्देश दिया। साथ ही अराजक तत्वों को चिन्हित करते हुए उनके विरुद्ध निरोधात्मक कार्यवाही करें। पुलिस अधीक्षक महोदय भी दोनो पक्षों को संबोधित करते हुए परस्पर भाईचारे के साथ आगामी पर्वों को मनाने की अपील की। कहा कि परम्परागत आयोजनों की पूर्वानुमति ले लें। किसी नवीन परंपरा की शुरुआत न करें। जुलूस आदि से अराजक तत्वों को दूर रखें। किसी प्रकार की आशंका उत्पन्न होने पर तत्काल पुलिस को सूचित करें। सोशल मीडिया पर किसी प्रकार की भ्रामक खबर/अफवाह न फैलाएं और न ही ऐसी खबरों के प्रभाव में आएं। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर पुलिस की कड़ी नजर है और आपत्तिजनक अथवा भ्रामक खबर पोस्ट करने पर कठोर कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने पुलिस अधिकारियों से संवेदनशील स्थलों को चिन्हित करते हुए कड़ी नजर रखने और आवश्यक सुरक्षा इंतजाम सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।उन्होंने पुलिस अधिकारियों को सतर्क और सक्रिय रहने का निर्देश दिया। साथ ही बाजारों में सादी वर्दी में पुलिस वालों को निगरानी हेतु तैनात करने का निर्देश दिया। इससे पूर्व दोनों समुदायों के प्रबुद्ध जनों ने अधिकारियों के समक्ष अपनी बातों को रखा। दोनों समुदायों के लोगों ने वरिष्ठ अधिकारियों को अश्वस्त किया कि आगामी त्यौहारों को परस्पर सद्भावना व भाईचारे के साथ मनाया जाएगा। बैठक का संचालन शमशुल हुदा ने किया। बैठक में अपर जिलाधिकारी डॉ प्रशांत कुमार वर्मा, सभी एसडीएम और सीओ सहित अन्य संबंधित प्रशासनिक व पुलिस अधिकारी उपस्थित रहे।

चौरी चौरा में पूर्वांचल पत्रकार एसोसिएशन की बैठक सम्पन्न, पत्रकारों की समस्याओं पर हुई गहन चर्चा

एम एम खान उर्फ फिरोज मंडल ब्यूरो गोरखपुर

चौरी चौरा। पूर्वांचल पत्रकार एसोसिएशन तहसील इकाई चौरी चौरा की अगस्त माह की मासिक बैठक तहसील परिसर में हर्षोल्लास के साथ सम्पन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता कर रहे तहसील अध्यक्ष योगेंद्र मौर्य ने कहां की संगठन में सदस्यों की सक्रियता से ही संगठन को ऊंचाइयों पर पहुंचाया जा सकता है मुख्य अतिथि एम एम खान उर्फ फिरोज मंडल सचिव ने कहा कि पत्रकार समाज का दर्पण होता है वह अपने लेखनी के बल पर समाज में व्याप्त समस्याओं को सरकार तक पहुंचाता है। विशिष्ट अतिथि दीपक कुमार रहे। बैठक में प्रदेश अनुशासन समिति के महासचिव सुमेरनाथ पाण्डेय ने संगठन की एकजुटता पर बल दिया । बैठक में बड़ी संख्या में पत्रकार उपस्थित रहे।

बैठक में संगठन की आगामी योजनाओं पर विचार–विमर्श किया गया। पत्रकारों को आने वाली समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की गई और उनके समाधान हेतु ठोस कदम उठाने पर बल दिया गया। समाज में पत्रकारों की भूमिका और सामाजिक जिम्मेदारियों पर भी गहन विचार विमर्श किया गया । बैठक में यह भी तय किया गया कि पत्रकारों की समस्याओं को लेकर धरना–प्रदर्शन का सहारा लिया जाएगा ताकि शासन–प्रशासन तक उनकी आवाज पहुँच सके।साथ ही, संगठन के साथी केश्वर गौंड की व्यक्तिगत समस्या पर भी विशेष रूप से विचार किया गया और संगठन ने उन्हें हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। बैठक के दौरान संगठन के कोष और भविष्य की योजनाओं पर भी चर्चा हुई।

इस अवसर पर ओम प्रकाश यादव अरविंद ओझा डॉ जामीर अंसारी रवि प्रकाश द्विवेदी, विनोद पासवान, धर्मेंद्र पटवा, महेश कुमार, आशुतोष कुमार पांडे, अभिषेक प्रजापति, दुर्गेश कुमार, समीर कुमार, अजय यादव, वसीम हक सिद्दीकी, केश्वर गोंड, कृष्ण कुमार, इसरार खान, सतीश कुमार, विकास राव, जमीर अंसारी, रजत कुमार शुक्ला, रामसेवक पासवान, योगेंद्र यादव समेत कई पत्रकार मौजूद रहे।

एसपी के निर्देशन, एएसपी के मार्गदर्शन में प्रभारी यातायात मय टीम द्वारा महराजगंज में लोगों को यातायात जागरूकता के नियमों के बारें में जागरूक किया

एम एम खान उर्फ फिरोज मंडल ब्यूरो गोरखपुर

आज दिनांक 31/08/2025 को यातायात पुलिस द्वारा नगर क्षेत्र के विभिन्न बस, टैक्सी, टैम्पो व ई रिक्शा स्टैंड के वाहन चालकों और यात्रियों को पम्पलेट बांटकर यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया गया और बताया गया की सदैव अपने बाएं तरफ से चलें, रॉन्ग साइड से वाहन ना चलाये, क्षमता से अधिक सवारी ना बैठाये, शराब पीकर वाहन ना चलाएं तथा वाहन चलाते समय सदैव यातायात नियमों का पालन करें।

कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही से सदर विधायक सुनील दत्त द्विवेदी की फर्रुखाबाद में खाद की कमी नहीं

कमल कांत दुबे जिला संवाददाता फर्रूखाबाद

सदर विधायक मेजर सुनील दत्त द्विवेदी ने प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप से वार्ता कर जिले में खाद की उपलब्धता को लेकर विस्तार जानकारी प्राप्त की उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रदेश सरकार किसानों की जरूरत के प्रति सदैव तत्पर है तथा जिले में उड़िया डीएपी और एनपीके की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी विधायक ने कहा कि कृषि मंत्री ने भरोसा दिलाया है कि किस को का डी समय पर और पर्याप्त मात्रा में फर्रुखाबाद जिले में 10794 मीट्रिक टन एनपीके का भंडार है इसमें से बड़ी मात्रा पहले ही किसानों तक पहुंच चुकी है उन्होंने बताया कि कानपुर मंडल में सबसे अधिक खाद का स्टॉक फर्रुखाबाद जिले को मिला है मंडल में 41283 मीट्रिक 10 उड़िया में से 7400 मीट्रिक टन तथा 41007 मीट्रिक टन डीएपी में से 13025 मीट्रिक टन का भंडार फर्रुखाबाद में है मेजर सुनील द्विवेदी ने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों को किसी भी तरह की समस्या नहीं होने देंगे

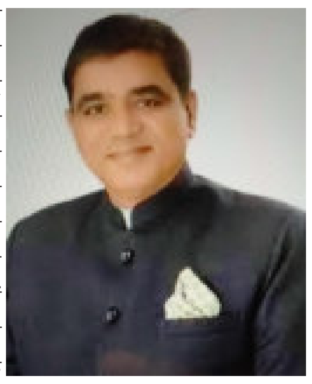

मुख्यमंती योगी की तरफ से फर्रुखाबाद को 5070 करोड़ का मिला तोहफा फर्रुखाबाद में लगेगी बीयर बनाने की फैक्ट्री

कमलकांत दुबे जिला संवाददाता।
फर्रूखाबाद

जिले को औद्योगिक हब बनाने के लिए प्रदेश सरकार लगातार प्रयासरत है कैबिनेट की बैठक में योगी सरकार ने पहले से यहां बन रहे एल्कोहल और स्टार्च संयंत्र की मंजूरी दे दी है कंपनी जिले में 570 करोड़ का निवेश करेगी युवाओं को रोजगार मिलेगा तो वही मक्का और आलू किसानों के भी दिन बदलेंगे युवाओं को मिलेगा रोजगार मक्का और आलू किसानों के भी बदलेंगे दिन इस प्लांट के लगने से फर्रुखाबाद के व्यापारी और युवाओं ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का धन्यवाद किया।

अवैध रूप से संचालित पनह पाली क्लीनिक

जनपद बहराइच नानपारा बाईपास अवैध रूप से संचालित पनह पाली क्लीनिक अवैध रूप से मरीज को भर्ती कर इलाज किया जाता है और मोटी रकम वसूल की जाती है मौके पर मीडिया कर्मी की टीम पहुंची तो अस्पताल में मरीज तो दिखाई दिए परंतु डॉक्टर नदारत मिले और पनहा पाली क्लीनिक डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव डॉक्टर प्रियंका पांडे, डॉक्टर बबलू सलमान , डॉक्टर नूर मोहम्मद, डॉक्टर गयान दीप तिवारी, का बैनर लगा हुआ हैं मौके पर कोई भी डॉक्टर नहीं मिला। अवैध रूप से संचालित है कोई रजिस्ट्रेशन नहीं मिला सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सभी प्रकार के इलाज किए जाते हैं डिलीवरी और ऑपरेशन भी किया जाता है मरीज से मोटी रकम वसूल की जाती है उत्तर प्रदेश सरकार जहां स्वास्थ्य व्यवस्था बेहतर बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है कुछ लोग सरकार की छवि धूमिल करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। ज़िला अधिकारी द्वारा शासन प्रशासन को अवगत कराया है कि फर्जी अस्पताल संचालक पर रोक लगाई जाए। ज़िला स्वास्थ्य अधिकारी इन पर कब कारवाई क्या इसी प्रकार जनता को लुट रहे गा कब होगी करवाई होगी।

पीड़ित का आरोप विपक्षी आए दिन मारपीट और गाली गलौज करता है जान से मारने की धमकी देता है अजहर हुसैन सलमान खान पुत्र राजा हुसैन फातिमा पत्नी अजहर हुसैन पीड़ित प्रताड़ित हो कर लगा रहा की है न्याय की गुहार थाना क्षेत्र अंतर्गत चिनहट कोतवाली लखनऊ

ब्यूरो रिपोर्ट रामेश्वर सिंह भदौरिया

मामला गौरव कुंज निजामपुर मल्हौर चिनहट का रहने वाला है विपक्षी अजहर हुसैन सलमान खान पुत्र अजहर हुसैन फातिमा पत्नी अजहर हुसैन यह चारों हमारे घर के सामने रहते हैं कई बार घर में घुसकर मारने पीटने का प्रयास किया है विपक्षी सलमान खान ने जान से मारने की धमकी दी है आए दिन बद्दी बद्दी गलियां गलौज करते हैं 01/09/25 को लगभग 5रू00 से 6रू00 तक गालियां देते हैं शायमा खान ने कई बार कोर्ट से फर्जी नोटिस भेजती रहती हैं और हमारे ऊपर मानहानि का दवा 5 करोड़ का ठोक दिया है और विपक्षी धारदार हथियार ले कर हम को जान से मारने की नीयत से घूमता है हमें और हमारे परिवार विपक्षी से खतरा है विपक्षी ने जो गाली गलौज मारपीट की है जिसका वीडियो साक्षी हमारे पास मौजूद है विपक्षीगढ़ आय दिन मारपीट करने पर आमदा रहता है साइमा खान ने फर्जी केस दर्ज कराने का प्रयास की है लेकिन कोई ठोस सुबूत न होने पर करवाई न हो पाई है तो अधिवक्ता का धोस दिखाकर रोज बवाल करता है आखिरकार इन चारों से पूछा जाए हमको और हमारे परिवार को क्यों गाली देते हैं जबकि हमारा इन चारों से कोई विवाद नहीं है फिर भी यह लोग ऐसा क्यों करते हैं अतः श्रीमान जी से निवेदन है मामले को संज्ञान में लेकर उचित कार्रवाई करने की कृपा करें।

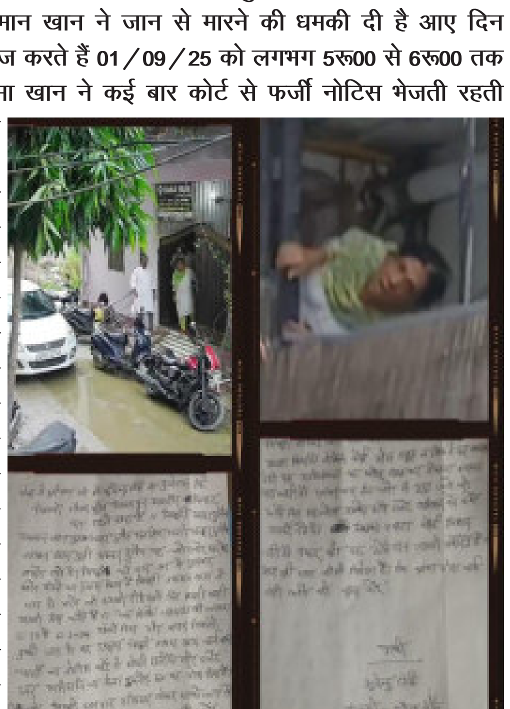

जनता दर्शन में एसपी द्वारा सुनी गई जन समस्याएं

ख़ास रिपोर्ट रामेश्वर सिंह भदोरिया ज़िला ब्यूरो चीफ़ हिंदी राष्ट्रीय समाचार पत्र जनता का सच पत्र

बहराइच। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा जनता दर्शन में आये फरियादियों की समस्याएं/शिकायतों को सुना गया। जनसुनवाई के दौरान प्राप्त शिकायतों/प्रार्थना पत्रों के सम्बध में सम्बन्धित अधिकारियों/थाना प्रभारियों को शीघ्र एवं गुणवत्तापूर्ण जाँच कर निस्तारित करने हेतु आदेशित किया गया।

गरीबों के आवास के सपने को साकार कर रही प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण

जिले के 190348 व्यक्तियों का पूरा हुआ आवास का सपना

ख़ास रिपोर्ट रामेश्वर सिंह भदोरिया ज़िला ब्यूरो चीफ़ हिंदी राष्ट्रीय समाचार पत्र जनता का सच पेपर पत्र

बहराइच। मानव जीवन में आवास का महत्व शारीरिक सुरक्षा और मूलभूत आवश्यकता की पूर्ति से लेकर मानसिक स्वास्थ्य, सामाजिक जुड़ाव और आर्थिक स्थिरता तक व्यापक है। एक सुरक्षित घर किसी व्यक्ति अथवा परिवार को मौसम, अपराध और अन्य खतरों से बचाने के साथ–साथ बुनियादी सुविधाएं भी प्रदान करता है। ईट गारे से तैयार की गई संरचना जिसे कि आमभाषा में घर कहा जाता है, यह परिवारों को एक साथ रहने, संबंध बनाने और मानसिक विकास के लिए एक स्थिर वातावरण प्रदान करता है। इसके अलावा, आवास आर्थिक विकास का एक महत्वपूर्ण इंजन है और सामाजिक प्रतिष्ठा व स्थिरता से जुड़ा है।

मानव जाति के आवास के महत्व को देखते हुए केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2024 तक ''सभी को आवास'' उपलब्ध कराने की प्रतिबद्धता के साथ इन्दिरा आवास योजना को 01 अप्रैल 2016 से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में पुर्नगठित कर दिया गया है। सभी पात्र लोगों को आवास उपलब्ध हो सकें इसके लिए आवास प्लस की सूची संतृप्त होने के उपरान्त शासन द्वारा पुनः आवास प्लस 2018 की सूची को आगे बढ़ाते हुए सर्वे का कार्य कराया गया है, जिसमें जिले के 265184 लाभार्थियों का सर्वे किया गया है जिसका विभिन्न स्तर पर सत्यापन की कार्यवाही करायी जा रही है। शीघ्र ही स्थायी पात्रता सूची तैयार होने पर सभी पात्र वंचित व्यक्तियों को भी आवास का लाभ दिया जायेगा।

आवास प्लस सूची के आधार पर तैयार की गई पात्रता सूची में सभी बेघर परिवारो और कच्चे तथा जीणशीर्ण मकानो में रह रहे पात्र व्यक्तियों को आवास उपलब्ध कराने का प्राविधान हैं। जनपद में विगत 09 वर्षों में प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण के लाभार्थियों की बात की जाये तो कुल 190384 व्यक्तियों को आवास की सुविधा प्रदान की गई है। वर्षवार निर्मित आवासों की बात की जाये तो वित्तीय वर्ष 2016–17 में 24679, वर्ष 2017–18 में 22153, वर्ष 2018–19 में 19269, वर्ष 2019–20 में 10878, वर्ष 2020–21 में 35472, वर्ष 2021–22 में 23680, वर्ष 2022–23 में 31779, वर्ष 2023–24 में 16238 तथा वर्ष 2024–25 में 6226 व्यक्तियों के आवास का सपना पूरा हो चुका है।

,प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण अन्तर्गत आवास का निर्माण 25.00 वर्ग मीटर में निर्धारित डिजाइन के अनुसार किया जायेगा। जिसमें एक कमरा, बरामदा एवं एक रसोई का निर्माण किया जायेगा। आवास की ईकाई लागत रू. 1,20,000=00 निर्धारित है जिसमें प्रथम किश्त के रूप में रू. 40,000=00, द्वितीय किश्त के रू. 70,000=00 एवं तृतीय किश्त रू. 10,000=00 एफ.टी.ओ. के माध्यम से खातें में अन्तरित किया जाता है। इसके अतिरिक्त मनरेगा के अन्तर्गत 90 दिनो की मजदूरी सीधे लाभार्थी के खाते में स्थानांतरित किये जाने का प्राविधान है। अभिसरण (कन्वर्जेस) के अन्तर्गत आवासों को शौचालय, विद्युत कनेक्शन, एल.पी.जी. कनेक्शन, हर घर नल से जल कनेक्शन एवं एस.एच.जी. से भी आवास लाभार्थी को लाभान्वित किया जाता है। लाभार्थी द्वारा आवास का निर्माण स्वयं कराया जाता है।

चुनाव न लड़ने वाले पंजीकृत राजनैतिक दलों की मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने की सुनवाई

स्टेट ब्यूरो चीफ अब्दुल नासिर जनता का सच समाचार पत्र।

बहराइच । सुनवाई में 51 पंजीकृत राजनैतिक दलों में से 17 राजनैतिक दल रहे उपस्थित उ0प्र0 राज्य के पते पर पंजीकृत 121 राजनैतिक दलों को विगत छः वर्षों से चुनाव में प्रतिभाग न करने के कारण जारी हुआ था कारण बताओ नोटिस पंजीकृत राजनैतिक दल अपना ईमेल,मोबाइल नंबर तथा वर्तमान पता अपडेट रखेरू मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा बहराइच भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री नवदीप रिणवा ने प्रदेश के पते पर पंजीकृत ऐसे राजनैतिक दल जो विगत छः वर्षों से प्रत्यक्ष रूप से लोक सभा एवं विधान सभा के चुनाव में प्रतिभाग नहीं कर रहें थे उनके प्रतिनिधियों के साथ बुधवार दिनांक 03 सितम्बर, 2025 को मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में सुनवाई की। उन्होंने प्रत्येक दल द्वारा प्रस्तुत किए गए अंशदान रिपोर्ट,वार्षिक लेखा परीक्षण (ऑडिट) रिपोर्ट एवं निर्वाचन व्यय विवरण जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेजों का गहन परीक्षण किया और सभी दलों के मोबाइल नंबर,पंजीकरण संख्या,वर्तमान पता व ईमेल की भी जांच की। मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा ऐसे दलों के प्रतिनिधियों को अपना प्रत्यावेदन,शपथपत्र एवं अन्य आवश्यक अभिलेखों के साथ सुनवाई के दौरान कार्यालय में उपस्थित होने के निर्देश दिए गए थे। उन्होने सुनवाई के लिए प्रदेश के पते पर पंजीकृत 121 राजनैतिक दलों को कारण बताओं नोटिस जारी किया था, इसमें से 03 सितम्बर को 51 राजनैतिक दलों को सुनवाई के लिए बुलाया गया था,जिसमें से 17 पंजीकृत राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों ने सुनवाई में प्रतिभाग किया। मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा 02 एवं 03 सितम्बर को की गयी सुनवाई में 121 राजनैतिक दलों में से 55 राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों ने प्रतिभाग किया और मुख्य निर्वाचन अधिकारी के सम्मुख उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत किया। सुनवाई के दौरान मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि प्रत्येक दल को प्रतिवर्ष 30 सितम्बर तक अपनी अंशदान रिपोर्ट तथा 31 अक्टूबर तक अपने आय–व्यय की आडिट रिपोर्ट देना अनिवार्य है। इसी प्रकार लोकसभा चुनाव के बाद 90 दिनों में तथा विधानसभा चुनाव के बाद 75 दिनों में अपने आय व्यय का ब्योरा भी देना है। प्रत्येक दल को चंदे के रूप में प्राप्त 20 हजार रुपए से अधिक के अंशदान की रिपोर्ट देनी है। उन्होंने कहा कि सभी दलों के प्रतिनिधियों को अपनी पार्टी का ईमेल,मोबाइल नंबर तथा वर्तमान पता को अपडेट रखना होगा, जिससे कि आयोग के निर्देशों व अन्य तथ्यों की जानकारी को समय से उपलब्ध कराया जा सके। बुधवार को हुई सुनवाई में गदर पार्टी प्रतापगढ़, नवचेतना पार्टी मैनपुरी, नवीन समाजवादी दल प्रयागराज, निस्वार्थ सेवा राष्ट्र सेवा पार्टी प्रयागराज, पूर्वांचल क्रांति पार्टी जौनपुर, राष्ट्रवादी इंसान पार्टी प्रयागराज, राष्ट्रवादी समाज पार्टी कानपुर नगर, राष्ट्रीय बंधुत्व पार्टी प्रयागराज, आम जन क्रांति पार्टी इटावा, राष्ट्रीय लोकतंत्र दल हापुड, राष्ट्रीय मानव विकास पार्टी अमरोहा, सामूहिक एकता पार्टी कानपुर नगर, सर्वप्रिय समाज पार्टी इटावा, सत्य शिखर पार्टी अयोध्या, यूथ सोशलिस्ट पार्टी मुरादाबाद, युवा अनुभव पार्टी गोरखपुर, भारतीय युवा स्वाभिमान पार्टी औरैया जिले में पंजीकृत राजनैतिक दलों के अध्यक्ष व महासचिव उपस्थित रहे।

परिवार परामर्श केन्द्र' द्वारा आपसी परिवारिक विवाद को समाप्त कराकर 03 परिवारों में सुलह कराते हुए परिवारों को टूटने से बचाया

ख़ास रिपोर्ट रामेश्वर सिंह भदोरिया ज़िला ब्यूरो चीफ़ हिंदी राष्ट्रीय समाचार पत्र जनता का सच पेपर

बहराइच। आवेदिका द्वारा आपसी पारिवारिक विवाद के सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक महोदय के समक्ष सुलह हेतु प्रार्थना पत्र दिया गया, जिसके निस्तारण हेतु पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा प्रभारी परिवार परामर्श केन्द्र को निर्देशित किया गया। परिवार परामर्श केन्द्र द्वारा शिकायतकर्ता की शिकायतों को विस्तारपूर्वक सुनकर–समझकर द्वितीय पक्ष से सम्पर्क करके उन्हें पुलिस कार्यालय स्थित परिवार परामर्श केंद्र बुलाया गया तथा दोनों पक्षों को समझाया गया, जिसके परिणामस्वरूप दोनों पक्षों द्वारा भविष्य में आपस में लड़ाई–झगड़ा न करने तथा परिवारिक कर्तव्यों का पालन करते हुए खुशी–खुशी साथ रहने की बात कही गयी। आपसी सुलह होने पर दोनों पक्षों को एक दूसरे के साथ आपस में सामंजस्य स्थापित कर परिवारिक दायित्यों को सही प्रकार से निर्वहन करने हेतु सलाह दी गई।

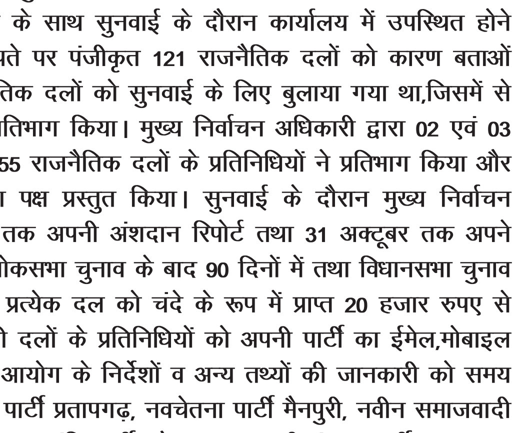

उ0नि0 रमाशंकर मिश्र, म0आ0 गिरजावती यादव, म0आ0 निशी त्रिवेदी, म0का0 सविता मिश्रा, म0का0 छाया द्विवेदी

डॉ. शक्ति सिंह साधू (प्रधान सम्पादक), डॉ. प्रवीण (प्रबंध सम्पादक), एडवोकेट शैलेन्द्र श्रीवास्तव (कानूनी सलाहकार), राकेश अग्रवाल (जिला ब्यूरो उत्तर प्रदेश) अब्दुल नासिर स्टेट ब्यूरो उत्तर प्रदेश

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक शक्ति सिंह द्वारा राज तरूण आफसेट, एल0जी0एफ0 5–14, अंसल सिटी सेंटर, हजरतगंज, लखनऊ– 226001 से मुद्रित तथा 486/238–डी, डालीगंज, निरालानगर, जनपद लखनऊ–226020 से प्रकाशित।

सम्पादक– शक्ति सिंह मो0 7052608007 नोटः समाचार पत्र से संबंधित समस्त विवादों का न्याय क्षेत्र लखनऊ न्यायालय होगा।